

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार



हमारा भाग्य हमारे कर्म और हमारी इच्छा से बनता है, और खुशी हमारे अपने कर्मों से आती है।

बीके शिवानी दीदी

वर्ष-09, अंक - 04 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 19 नवम्बर 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

छपरी गैंग के निशाने पर समाज के ही युवक-युवतियां, आदिवासी संगठन सुधार के लिए आगे आए

माही की गूंज, झाबुआ।

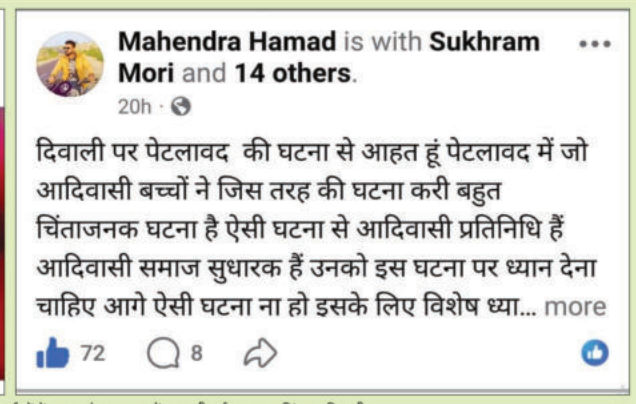
संजय भटेवरा

सोशल मीडिया के बढ़ते चलन और महंगे शोक, बाईक राइडिंग तथा शराब के नशे में मद मस्त हो कर भटक चुका ग्रामीण अंचल का किशोरावस्था के युवा अब पूरे समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। लगातार बढ़ती इन युवाओं की हरकतों से परेशान कई सामाजिक संगठनों व आम जनता ने खुल कर इनका विरोध कर इन पर सामाजिक व कानुनी कार्रवाई की मांग की है। इन टीन एजर युवाओं की बेल बॉटम पेंट, अटपटी कटिंग, शर्ट के खुले बटन, हाथ में महंगा मोबाइल, महंगी बाईक, सिगरेट के छल्ले उड़ाते एक हाथ में बियर का टीन और फिर हुडदंग मचाते हुए हाट बाजारों में आने वाली युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले युवा छपरी नाम से फेमस हो चुके है। अब ये धीरे-धीरे समाज के लिए भी नासूर बनते जा रहे है। इनकी मदहोशी का आलम ये है कि ये लोग पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं है। कई मेले और सार्वजनिक आयोजन इन छपरी टाइप लड़कों के आतंक की भेट चढ़ चुके है जहां आयोजक अब आयोजन करने में सोच रहे है। तो जो आयोजन हो रहे है उनमें लोग जाने से कतरा रहे है। इनके बढ़ते आतंक का शिकार आदिवासी समाज की युवतियां होती है जिनके साथ छेड़छाड़ के वीडियो सोशल मिडिया पर भरे पड़े हैं।

व्यापारी के यहां तोड़फोड़, पुलिस टीम पर हमला

अब ये छपरी गैंग अपनी हदें पार कर करते हुए विरोध करने वालो के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे है। जिसका नजारा पेटलावद में गाय गोहरी पर्व के समय देखने को मिल चुका। मेला हो या कोई भी सार्वजनिक आयोजन ये छपरी गैंग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए एक-दूसरे गुट पर हमला कर विवाद करने पर उतारू हो जाते है। इस दौरान जमकर विवाद हुए, तोडफोड़ ओर मारपीट की जाती है, जिससे कई व्यापारीयो को भी नुकसान पहुंचाया। सुरक्षा व्यवस्था में लगी पेटलावद पुलिस के जवान भीड़ में हुड़दंग कर रहे लोगों को अलग करते रहे लेकिन नशे में चूर ये छपरी युवा पुलिस पर ही हमला करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि, हुड़दंग कर रहे युवाओं को समझा रहे पुलिस जवान पर एक युवा ने बेल्ट से हमला कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया लेकिन पुलिस को भी चकमा देकर फरार हो गया।





सोशल मीडिया पर चिंतनकर्ताओं ने समाज के इन युवाओं द्वारा की गई घटना पर चिंता जाहिर की।

टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने वालों के पीछे नई पीढ़ी

आदिवासी समाज के कई युवा अपने हुनर और टेलेंट के दम पर सोशल मिडिया पर छाए हुए हैं और पैसा कमा रहे है। उनका बदला लाइफ स्टाइल और स्टेट्स से प्रभावित अंचल का युवा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के लिए ऊटपटांग हरकते कर रहा है। आसान किस्तों पर मिल रही महंगी बाईकें और मोबाइल ने इन युवाओं को पंख लगा दिए जिसके बाद वायरल होने की सनक ने इन युवाओं का जीवन बदल दिया। जिन हाथों में किताबें होनी थी उन हाथों में बाईक और मोबाइल है जो विवाद की जड़ बनता जा रहा है। टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रहे है युवाओं की तरह आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ता अपना रहे है।

सुधार की जरूरत, आदिवासी संगठनों को आना होगा आगे

बिगड़ती युवा पीढ़ी को सुधार की आवश्यकता आन पड़ी है क्योंकि समय रहते सही दिशा नहीं दिखाई गई तो ये भटका हुआ कब अपराध की दिशा में आगे बढ़ कर समाज के लिए खतरा बन सकता है। आदिवासी समाज से जुड़े लगभग सभी संगठनों ने भी इन छपरी गैंग पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जरूरी सुधार के लिए उनको आगे आना होगा, हुड़दंग करने वाले इन युवाओं को चिन्हित करना होगा, क्योंकि ज्यादातर युवा स्कूल और हॉस्टल में रहने वाले भी हो सकते है। साथ ही युवतियों पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि स्कूली युवतियों का बड़ा जमावड़ा बाजारों में होता है, इनके साथ ग्रामीण अंचल की युवतियां भी होती है जो इस छपरी गैंग के निशाने पर होती है। कई बार युवकों के साथ युवतिया भी आपस में लड़ाई करती दिखाई देती है। जिसके वीडियो से सोशल मिडिया भरे पड़े है। गाय गोहरी पर्व पर हुए हुड़दंग के बाद पेटलावद पुलिस द्वारा कुछ छपरी युवाओं का जुलूस निकाल कर कड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की है लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क देखने को जिले में नहीं मिला ओर अब हाट बाजारों और मेलो में इसका आतंक बना हुआ है। जिसके चलते कई स्थानों पर लगने वाले मेलों के लिए पुलिस की ओर से अनुमति तक जारी नहीं की जा रही।



छपरी गैंग का निकाला जुलुस।

मुठभेड़ में लश्कर कमांडर ढेर, अमित शाह ने की जवानों की तारीफ

नई दिल्ली, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से यह सफलता मिली है। उन्होंने जवानों के साहस और उनकी कार्रवाई की प्रशंसा की।



शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि बुधवार तड़के चलाए गए अभियान में लश्कर का घाटी में सक्रिय आखिरी स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट मारा गया। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ स्थल से आतंकवादी का शव और हथियार बरामद हुए हैं। लतीफ कुलगाम के खेरवान का निवासी था। इससे एक दिन पहले उसके साथी आतंकवादी उमर निसार को भी कुलगाम में मार गिराया गया था।

भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना के बाद सेना और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आतंकियों को घेर लिया। उन्होंने आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे तक अभियान जारी रखने की बात कही।

वहीं, जदयू के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष जीएम शाहीन ने भी सुरक्षा बलों की सराहना की। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बातचीत तभी संभव है, जब दोनों पक्ष गंभीर हों। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियां जारी रहने पर बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में केंद्र सरकार सक्षम है।

भारत की अर्थव्यवस्था के साथ पूंजी बाजार भी तेजी से बढ़ रहा - पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश का पूंजी बाजार भी लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने विश्व शेयर बाजार महासंघ की 65वीं आमसभा और वार्षिक बैठक के आयोजन पर राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और महासंघ को बधाई देते हुए इसमें शामिल वैश्विक प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत का पूंजी बाजार कंपनियों को धन जुटाने, कारोबार का विस्तार करने और विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर रहा है। म्यूचुअल फंड जैसे निवेश माध्यमों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और देश में निवेश का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शेयर बाजार से जुड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बन रहे हैं।



मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने वित्तीय व्यवस्था को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैंकिंग, बीमा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से लाखों लोग औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हैं। जनधन-आधार-मोबाइल व्यवस्था और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाओं ने आम लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान बनाई है। तकनीक आधारित सुधारों और निवेश मंचों की सरल उपलब्धता से भी पूंजी बाजार में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नई तकनीकों के कारण तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इनसे विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि तकनीक भले ही बाजारों के विकास को नई दिशा दे, लेकिन वित्तीय व्यवस्था की मजबूती और दीर्घकालीन विकास के लिए लोगों का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है।

क्या यही सुशासन और डबल इंजन की सरकार है...?

माही की गूंज, खवासा/झाबुआ।

चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करके जनता का वोट तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन चुनाव के बाद वे सारे वादे हवा हवाई हो जाते हैं 2014 के चुनाव के समय तात्कालिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने सुशासन की परिभाषा बतलाते हुए कहा था कि, सुशासन वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार स्वयं पात्र व्यक्ति तक पहुंचकर उसे सरकारी योजना का लाभ दिलाए न की पात्र व्यक्ति सरकारी कार्यालयो के चक्कर लगाए। वर्तमान में नरेंद्र मोदी लगभग 13 वर्षों से





प्रधानमंत्री पद पर आसिन है तो क्या उनके कथनानुसार देश में सुशासन व्यवस्था लागू है...? क्या आम आदमी को अपने जरूरी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ रहे हैं...? ऐसा ही एक नारा 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से दिया गया था वोट डबल इंजन की सरकार के लिए दे ताकि विकास कार्य तेज गति से चल सके और मध्य प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार के लिए वोट दिया, लेकिन विकास कार्य तेजी से होने के बजाय आम जनता को अपने वाजिब कार्यों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है क्या यही डबल इंजन की सरकार है...?

हम बात कर रहे हैं खवासा क्षेत्र की जहां लंबे समय से पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की कमी है। यहां बारहमासी पेय जल संकट बना रहता है। वहीं सिंचाई के लिए भी पानी की कमी की वजह से किसान दो या तीन फसल नहीं ले पाते हैं। जिसके कारण यहां रोजगार का संकट है और जनवरी-फरवरी से ही क्षेत्र में पलायन शुरू हो जाता है जो की मानसून आने तक जारी रहता है। इस क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन का मुद्दा लगभग हर चुनाव में उठता है और रोजगार उपलब्ध कराने के तमाम दावे के बीच आज भी पलायन रुक पाना तो दूर और अधिक बढ़ता जाता है। पलायन के कारण क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित होता है यानी पानी की कमी का असर समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है। हाल ही में नर्मदा परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के करकमलो द्वारा किया गया जिसमें झाबुआ और आलीराजपुर जिले के कई गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन खवास क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिए किख् इस परियोजना में भी इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। यानी महज 1से2 किलोमीटर दूर जा रहे नर्मदा के पानी से खवासा का वंचित है। इसी प्रकार क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित माही नदी पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे रतलाम और धार जिले के सैकड़ो गांव को पेयजल मिलेगा लेकिन पास में स्थित खवासा क्षेत्र को यह पानी नहीं मिलेगा। यानी खवासा क्षेत्र के दोनों और 5 हजार करोड़ की दो बड़ी परियोजना है लेकिन खवासा क्षेत्र इससे अछूता है और यहां पर ''कुएं के किनारे प्यासा रहने'' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अपने आप को ठगा महसूस करने वाले खवासा क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए पिछले वर्ष दो बार रैली और धरने के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई लेकिन मोटी चमड़ी के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिससे आहत होकर क्षेत्रवासी इस बार आर-पार की लड़ाई के मुड में हैं। ज्ञापन देने के बाद 16 नवंबर से अनिश्चित कालीन धरना प्रारंभ हो गया है जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हो रहे हैं। धरने को व्यापक जनसंमर्थन मिल रहा है मंगलवार को व्यापारी संघ की बैठक भी धरना स्थल पर रखी गई जिसमें व्यापक विचार विमर्श और क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए धरने को समर्थन दिया गया। तथा शुक्रवार 20 नवंबर को एक दिनी हड़ताल रखने पर भी सहमति बनी। साथ ही नर्मदा-माही का पानी खवासा क्षेत्र में लाने के लिए किए जाने वाले प्रत्येक विरोध प्रदर्शन के लिए सहमति दी गई। अब शुक्रवार को खवासा नगर बंद रहेगा सभी की एक ही मांग है कि, खवासा क्षेत्र को इन दोनों परियोजना का लाभ मिले।

16 नवंबर से जारी धरना प्रदर्शन पर सूचना देने के बाद भी अभी तक प्रभावी रूप से कोई प्रशासनिक और न ही कोई राजनीतिक हलचल हुई। जिसके चलते क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि, इतने बड़े धरना प्रदर्शन को अनदेखा करना शासन प्रशासन की अकर्मण्यता को दर्शाता है जबकि दावा सुशासन का किया जा रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किए जा रहे इस विशाल धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाए, बच्चे व बुजुर्ग भी शामिल हो रहे हैं।

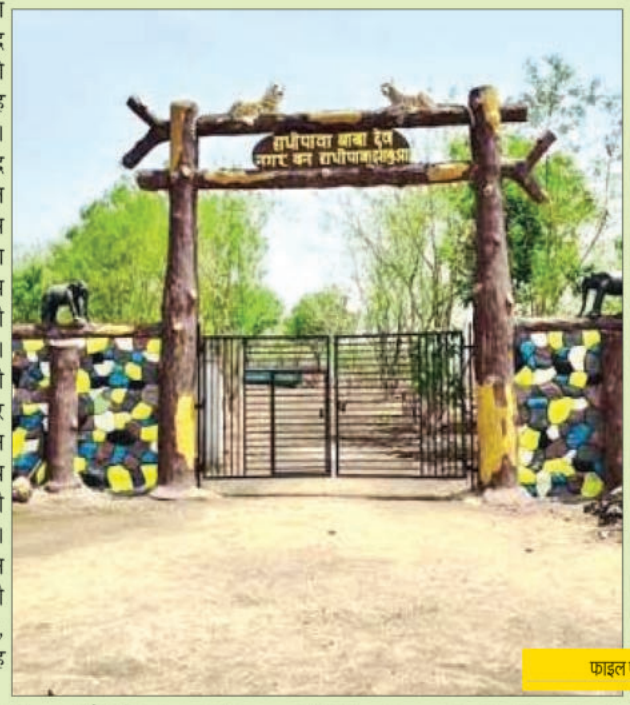
बुजुर्गों का कहना है कि, हमने लंबे समय तक क्षेत्र में जल संकट को देखा है आने वाली पीढ़ी को इस जल संकट से मुक्ति मिले जिसके लिए यह प्रयास जारी है। उनका कहना है कि, भाजपा के सुशासन के दावे में यह पानी बिना मांगे मिलना था लेकिन विडम्बना देखिए इतने बड़े धरने के बाद भी शासन-प्रशासन के कानों में जु तक नहीं रेंग रही है क्या सुशासन ऐसा होता है...?

सितम्बर में हुई हत्या के बाद लगातार महीनों तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था हाथीपावा

हाथीपावा पर आवश्य अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों पर बैठकें तो हो रही, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं

माही की गूंज, झाबुआ।

कुछ वर्षों पहले तक जिला मुख्यालय के समीप उजाड़ हाथीपावा की पहाड़ियों को कम ही लोग जानते थे, लेकिन 9 जुलाई 2017 के बाद इस स्थान ने ऐसी करवट ली कि, जिला तो जिला जिले के बाहर से आने वालों के मुंह पर भी हाथीपावा पहाड़ी का नाम चढ़ गया। अथक प्रयासों और वर्षों की मेहनत के बाद यह स्थान हाथीपावा पहाड़ियों को मिल पाया। 2017 में तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने 'हाथीपावा मॉर्निंग क्लब', जिला प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से इस बंजर पहाड़ी को हरा-भरा करने की मुहिम शुरू की थी। 2017 में शुरूआती दौर में इस बंजर पड़ी पथरीली पहाड़ी पर उपजाउ मिट्टी डलवाकर यहां 8 से 10 हजार पौधों का रोपण जन सहयोग से किया गया। समय के साथ पौधरोपण में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। पुलिस विभाग, वन विभाग और जन सहयोग के कड़े परिश्रम और वर्षों की तपस्या के बाद इन पहाड़ियों पर सुंदर, प्राकृतिक वन खड़ा हो गया और यह पहाड़ियां पर्यटन का केंद्र बन गई।





फाइल फोटो

हालांकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन के स्थानांतरित होने के बाद कुछ समय के लिए प्रशासन और वन विभाग ने यहां लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि हाथीपावा पर्यटन स्थल पर लगे बच्चों के मनोरंजन के साथ स्वाह हो गए और जो कुछ बचा कुचा था उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के एक दौरे के दौरान खुद जिला प्रशासन ने उखाड़कर फैंक दिया था। मगर पिछले कुछ समय से फिर इन हाथीपावा पहाड़ियों के आवश्यक अधोसंरचना विकास पर जिला प्रशासन द्वारा बैठकें की जा रही है। हालांकि वन विभाग अपने स्तर पर यहां कार्य करता रहा है मगर वह अब तक उंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ है। अब वर्तमान कलेक्टर योगेश तुकाराम समय ही बताएगा कि जिला प्रशासन इन पर कितना खरा उतरेगा।

हाथीपावा को पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप ग्रीन फील्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर सोमवार को कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथीपावा क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्थायी जल आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें मौजूदा जल स्त्रोतों की स्थिति, पंपिंग व्यवस्था, जल संग्रहण संरचना, पाइपलाइन विस्तार एवं विद्युत कनेक्शन जैसे आवश्यक कार्यों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अंतर्गत चार प्रमुख कार्य पैकेज प्रस्तुत किए गए। इनमें 30 फीट गहरे कुएं एवं पाइपलाइन संबंधी कार्य, ध्वजारोहण स्थल पर विद्युत कनेक्शन एवं मोनोब्लॉक पंप की व्यवस्था, 30 हजार लीटर क्षमता के नवीन संपवेल एवं पाइपलाइन निर्माण तथा नलकूप एवं पंप संबंधी कार्य शामिल हैं।

प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत जल स्त्रोतों के विकास एवं सुधार, पंप हाउस निर्माण, आवश्यक पाइपलाइन बिछाने, विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तथा नवीन नलकूप स्थापित करने जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। बैठक में प्रस्तावित कार्यों के तकनीकी परीक्षण, जल स्त्रोतों की क्षमता एवं गुणवत्ता की जांच, पाइपलाइन के मार्ग निर्धारण तथा विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही विकास कार्यों के दौरान हाथीपावा की प्राकृतिक सुंदरता, हरित आवरण एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। निर्माण कार्य इस प्रकार किए जाने पर बल दिया गया, जिससे पेड़-पौधों एवं प्राकृतिक ढलानों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे।

कलेक्ट्रोरेट सभाकक्षा में हुई इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु अधिकारियों और कलेक्टर महोदय ने नजर अंदाज कर दिया। असल में बैठक में रखे गए सारे प्रस्ताव और मुद्दे बाद में आते है। सबसे पहले जो मुद्दा होना चाहिए था वह था हाथीपावा पर्यटन की इन पहाड़ियों पर सुरक्षा का मुद्दा जिस पर न तो कलेक्टर ने कोई सवाल किए और न ही किसी अधिकारी ने इस पर कोई विस्तृत चर्चा की। जबकि इस बैठक में खुद जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार मौजूद थे।

पिछले कुछ वर्षों में हरी भरी होने के बावजूद हाथीपावा पहाड़ियां जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुई है। यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी बड़ा है। देखरेख के अभाव के कारण यहां कुछ सरारती तत्वों ने नुकसान भी पहुंचाया है। पेड़ काटने की घटनाएं भी सामने आई है। कड़ी निगरानी व रख-रखाव के अभाव में यहां प्रेमी युगलों का भी बहुत बोलबाला रहा है। पिछले दिनों सितम्बर माह में यहां पर एक शव बरामद किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि, कुछ लोगों ने उधारी मांगने के लिए युवक को हाथीपावा पहाड़ी पर बुलाया था और इसी कारण उसकी पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या होने के बाद यहां पर वन विभाग ने पुर्ण रूप से तालाबंदी कर दी थी। जिससे पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा था। दीपावली के करीब इस हाथीपावा पर्यटन स्थल को फिर से खोला गया। मगर अभी कुछ दिन ही हुए थे कि 14 नवम्बर को हाथीपावा पहाड़ी के तीन अलग-अलग हिस्सों में किन्ही सरारती तत्वों ने आग लगा दी थी। आग की लपटे और धुंआ देख हड़कंप की स्थिति बन गई थी लेकिन वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस आग पर काबू पा लिया।

अगर जिला प्रशासन वाकई इस हाथीपावा पर्यटन स्थल को पर्यटकों के लिए सुविधा जनक बनाना चाहता है तो यहां सबसे पहले सुरक्षा के इंतेजाम करना जरूरी है। जिला प्रशासन की योजनएं जब जमीन पर आएंगी तब आएंगी मगर इस वर्तमान समय में हाथीपावा की इन पहाड़ियों पर पर्यटकों की सुरक्षा का अभाव साफ -साफ नजर आता है। यह और बात है कि, घटना घटने के बाद प्रशासन लाठी लेकर निकलता है। किसी घटना या दुर्घटना के कारण पर्यटन स्थल को बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम करना ही समझदारी होगी। ताकि हाथीपावा की रोनक पर्यटकों से बनी रहे। पर्यटकों के मन में सुरक्षा को लेकर कोई संकोच न रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जिला प्रशासन की हाथीपावा को विकसित करने की योजना मिथक ही साबित होगी।

भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

माही की गूंज, पेटलावद।

जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हिन्दू जागरण मंच पेटलावद द्वारा महान क्रांतिकारी एवं जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग एवं राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में जनजातीय समाज को जागृत और संगठित करने का कार्य किया। तथा अपने समाज की संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और धर्मांतरण के प्रयासों का भी विरोध किया।

कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आत्मसात करने तथा समाज में जागरूकता, एकता और सांस्कृतिक चेतना बनाए रखने का संकल्प लिया।



छू लो आसमान : छात्र–छात्राओं ने लिया खेल प्रतियोगिता में भाग

माही की गूंज, पेटलावद।

संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने संकुल स्तर पर आयोजित छू लो आसमान खेल प्रतियोगिता में खो-खो एवं कबड्डी टीम से चयनित होकर तहसील स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया।

इस अवसर पर संकुल प्राचार्य मांगीलाल गरवाल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने पुलिस थाना पेटलावद का भ्रमण किया। थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया ने बच्चों को संबोधित करते हुए वर्तमान दौर में त्योहारों व बाजारों में होने वाले अभद्र व्यवहार और उसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि, आज का युवा महंगी गाड़ियां लेकर जगह-जगह दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है और युवा वर्ग बिना किसी काम के बाजारों में समय व्यर्थ कर रहा है। उन्होंने बच्चों से जीवन में अच्छे कार्यों पर ध्यान देने और अपने माता-पिता व गांव का नाम रोशन करने का आग्रह किया। साथ ही समस्त शिक्षक साथियों से निवेदन किया कि वे विद्यार्थियों को हाट-बाजारों व देर रात डीजे आदि में समय खराब करने से रोकें और पढ़ाई की ओर प्रेरित करें। थाना प्रभारी ने अपने सहयोगी पुलिस स्टाफ के साथ बच्चों को पूरे थाना परिसर का भ्रमण कराते हुए बंदी गृह, रिपोर्ट कक्ष व अन्य कक्षों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए है। उल्लेखनीय है कि संकुल स्तर पर कुल 24 बच्चों का चयन हुआ था, जिनमें से तहसील स्तर पर खो-खो, कबड्डी व 100 मीटर दौड़ में चयनित कुल 16 बच्चे अब जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।



जन्मशताब्दी वर्षः गायत्री परिजन हरिद्वार रवाना

माही की गूंज, पेटलावद।

माता भगवती देवी शर्मा जी के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में 21 एवं 22 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए गायत्री शक्तिपीठ से 51 गायत्री परिजनों का दल बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। बस प्रस्थान से पूर्व सभी परिजनों को तिलक लगाकर एवं शुभकामनाएं देकर विदाई दी गई। सभी परिजन इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विशेष उत्साहित नजर आए। यात्रा के दौरान गायत्री परिजन परम वंदनीया माताजी की जन्मभूमि आंवलखेड़ा, तपोभूमि मथुरा सहित विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात सभी परिजन हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचकर जन्मशताब्दी वर्ष के भव्य आयोजनों में सहभागिता करेंगे। 51 परिजनों का यह दल भी श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उमंग के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने के लिए रवाना हुआ है।



व्यापारी संघ ने किया धरने का समर्थन, शुक्रवार को खवासा बंद

माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोलंकी

कुकड़ीपाड़ा माही तट पर तलावड़ा माही पेयजल परियोजना का लाभ खवासा सहित क्षेत्र के ग्रामों को लाभ मिले, तथा नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जोकि खवासा के काकड़ तक पाइपलाइन होने के बावजूद खवासा क्षेत्र की उपेक्षा कर खवासा क्षेत्र को उक्त परियोजना से भी वंचित रखा जा रहा है। जिस हेतु खवासा सहित क्षेत्र के लोगों में निराशा है। तथा माही-नर्मदा मांगे खवासा क्षेत्र के बेनर के साथ खवासा सहित क्षेत्र के लोग खासकर महिलाएं भी तथा सर्व राजनीतिक नेता व जन प्रतिनिधि भी क्षेत्र को उक्त योजना का लाभ मिले जिस उम्मीद के साथ 16 नवंबर से बस स्टैंड के पास पुरानी प्राथमिक शाला परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

क्षेत्र के जनहित को देखते हुए उक्त धरने का समर्थन खवासा के सकल व्यापारी संघ ने तन-मन-धन से करते हुए शुक्रवार को खवासा ग्राम पूर्णतः बंद का निर्णय लिया है। मंगलवार रात्रि सकल व्यापारी संघ खवासा की एक वृहद बैठक अध्यक्ष नितिन मेलावत की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि, जनहित में किए जा रहे अनिश्चित कालीन धरने को सकल व्यापारी संघ खवासा तन-मन व धन से पूरा समर्थन देगा। धरने को समर्थन देते हुए 20 नवम्बर शुक्रवार को पूरे ग्राम के सभी प्रतिष्ठान (दूध एवं मेडिकल को छोड़कर) बंद रहने का आह्वान सकल व्यापारी संघ ने सामूहिक रूप से किया। तथा अर्थ सहयोग देने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही बंद के दौरान सभी व्यापारी वर्ग धरने में आकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाएंगे तथा उसके बाद भी प्रतिदिन धरना आयोजन के दौरान अपने समयानुसार समय निकालकर धरना स्थल पर उपस्थित होकर धरने का समर्थन करेंगे।

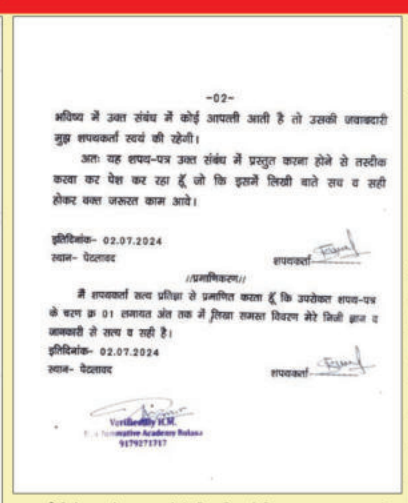
अध्यक्ष नितिन मेलावत के साथ समस्त सकल व्यापारी संघ ने अपील की है कि, सभी व्यापारी शुक्रवार को अपनी दुकान बंद रखें और धरने का समर्थन करें।



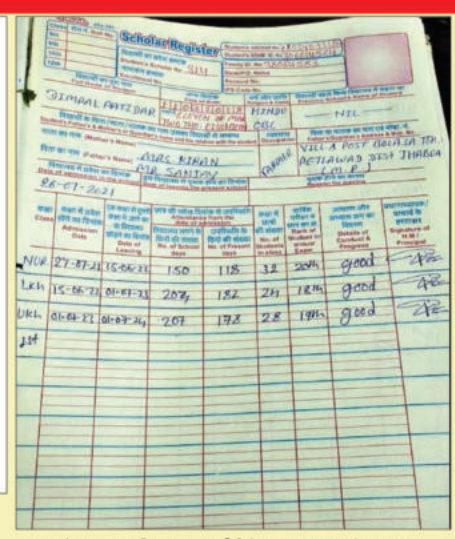
शिक्षा का अधिकार योजना में घोटाला, स्कूल छोड़ने के बाद फर्जी तरीके से निकलती रही राशि

कलेक्टर ने शासकीय राशि की हेराफेरी मामले में नहीं दिखाई रूची, हर शिकायत को जांच के नाम पर आगे बढ़ाया

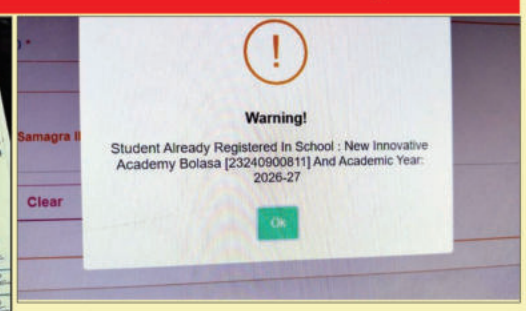




आरटीई योजना से नाम हटाने के लिए पिता ने दिया था शपथ पत्र इसके बाद भी नाम नहीं हटाने का आरोप।



2021 से 2023 तक लिया गया आरटीई योजना का लाभ, इसके बाद स्कूल बदलने के बाद भी योजना से नाम नहीं हुआ बाहर।



अपर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन के समय हुआ खुलासा, बालिका का ऑन लाइन नाम पुरानी स्कूल में ही दर्ज।

माही की गूंज, पेटलावद।

झाबुआ जिले के पेटलावद विकास खंड में आरटीई शिक्षा का अधिकार योजना में हेराफेरी का गंभीर मामला सामने आया है। पेटलावद के बोलासा गाँव में आरटीई योजना के तहत शिक्षा ले रही छात्रा के स्कूल छोड़ने के दो साल बाद भी आरटीई के तहत पैसे निकाले जाते रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि, जब अभिभावक ने इसकी शिकायत की तो सिस्टम ने मामले की गहराई से जाँच करने के बजाय इसे मांग श्रेणी बताकर बंद कर दिया।

पूरा मामला क्या है? शपथ पत्र लेने के बाद नाम नहीं कटा

बोलासा निवासी संजय पाटीदार की बेटी डिंपल पाटीदार ने 27 जुलाई 2021 से आरटीई के तहत न्यू इनोवेटिव एकेडमी स्कूल (डाइस कोड 23241900811, प्रपोजल आईडी 146262, स्कूल आईडी 811883, संकुल केंद्र बोलासा) में पढ़ाई शुरू की थी। बालिका का एडमिशन आरटीई योजना के तहत किया गया था लेकिन स्कूल की शिक्षा से असंतुष्ट होकर बालिका के पिता ने 2024-25 के लिए नाम कटवाकर दूसरे स्कूल माय स्माल वर्ल्ड एकेडमी, बोलासा में एडमिशन दिला दिया। संस्था बदलने के बाद बालिका के पिता ने आरटीई योजना का लाभ बंद करने की मांग की तो बीआरसी रेखा गिरी ने इस संबंध में बालिका के पिता का स्टाम्प पर शपथ पत्र भी लिया। जिसके बाद नाम आरटीई योजना से काटा जाना था जोकि नहीं काटा गया। स्कूल रिकॉड से प्रति वर्ष इसकी जानकारी भेजी गई जिसको नजर अंदाज किया गया।

अपर आईडी अपडेट करने पर खुला राज

हाल ही में जब परिजनों ने बालिका की नई संस्था माय स्माल वर्ल्ड एकेडमीश में अपार आईडी के लिए दस्तावेज अपडेट किए, तब पता चला कि डिंपल का नाम अभी भी पुराने स्कूल में आरटीई के पोर्टल पर चल रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बच्ची के नाम से इस सत्र को मिलाकर कुल तीन साल तक फर्जी तरीके से राशि निकाली गई है।

सीएम हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर दरबार तक चक्कर

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पहली शिकायत (27 अगस्त 2026) संजय पाटीदार ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत (क्रमांक 40272327) दर्ज कराई। लेकिन बिना किसी ठोस जाँच के 17 सितंबर को यह कहकर शिकायत बंद कर दी गई कि इसकी प्रकृति मांग श्रेणी की है। इसके बाद दूसरी शिकायत (18 सितंबर 2026) इसके बाद उन्होंने फिर से शिकायत (क्रमांक 40617978) दर्ज करवाई। आरोप है कि इस दौरान शिकायत बंद कराने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावक पर लगातार दबाव बनाया गया। कार्रवाई नहीं होने से शिकायतकर्ता ने कलेक्टर जनसुनवाई (6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर) मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 अक्टूबर को कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. बामनिया को जाँच सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 13 अक्टूबर को फिर आवेदन देने पर जाँच का जिम्मा अधिकारी वैशाली सोलंकी को सौंपा गया। जिसका भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर नवीनतम आवेदन (17 नवंबर 2026) कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट को पुनः आवेदन सौंपकर बालिका के नाम से निकाली गई पूरी राशि शासन के खाते में वापस जमा कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग की है।

दूसरी संस्था पर शिकायत बंद करवाने का दबाव, कलेक्टर के समक्ष भी नाराजगी की व्यक्त

जब बालिका ने वर्ष 2023-24 के बाद वह स्कूल छोड़ दिया था, तो उसका ऑनलाइन नाम पोर्टल से क्यों नहीं हटाया गया? संबंधित नोडल अधिकारियों और जाँच अधिकारियों ने बिना भौतिक सत्यापन के फर्जी निकासी में कैसे सहयोग किया? अब देखना यह होगा कि, कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट के पास पहुँचे इस नए आवेदन के बाद प्रशासन इस बड़े फर्जीवाड़े पर क्या ठोस कदम उठाता है। उधर पेटलावद विकास खंड की बीआरसी रेखा गिरी पर भी शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता संजय पाटीदार ने बताया कि, शिकायत से बौखलाई बीआरसी रेखा गिरी ने जिस दूसरी संस्था में मेरी बालिका पड़ रही है उस संस्था के प्रबंधक को धमकी देकर मेरी शिकायत बंद करवाने का दबाव कई बार बनाया गया ओर शिकायत बंद नहीं करवाने पर स्कूल पर कार्रवाई करने की धौंस तक दी गई। उधर बीआरसी रेखा गिरी ने इस विषय में कहा कि बच्ची का नाम पूर्व में ही काटा जा चुका है ओर भौतिक सत्यापन नहीं होने से भुगतान नहीं हुआ है। मामले की शिकायत के बाद जांच कर कलेक्टर को भेज दी गई है। पूरे मामले पर माही की गूंज के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रहीं है। आरटीई योजना में इस प्रकार की हेराफेरी के कई गम्भीर मामले जांच में सामने आ सकते है।

नहर के जल को व्यर्थ बहा रहे किसान, रात के अंधेरे में नहर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा



माही की गूंज, करवड़। अरुण पाटीदार

करवड़ क्षेत्र के किसान माही नहरो को क्षतिग्रस्त कर पानी रोड पर निकाल रहे हैं। माही परियोजना की नहर में बांध से पानी छोड़ दिया गया है। नहर से पानी लेकर किसान सिंचाई कर रहे हैं उन्हे आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं अनुविभागीय अधिकारी रितिका पाटीदार के निर्देशन में नहर का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में करवड़ क्षेत्र में कई जगह पानी के लिए नहर की तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में किसानों के ऊपर प्रशासन को कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए वही पीछे के किसानों को पानी लेने में बहुत समस्या आ रही है। इस दौरान माही नहर को क्षतिग्रस्त न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नाले, नदी, तालाब में अवैध रूप से पानी लेने व अवैध रूप से लिए गए विद्युत कनेक्शन की जांच पड़ताल की जा रही है।



राणा पूंजा मूर्ति स्थापना हेतु भूमि पूजन

माही की गूंज, पेटलावद।

इन दिनों नगर में अलग-अलग क्षेत्र में अपना योगदान देकर प्रेरणा स्त्रोत बने जन नायकों की प्रतिमा स्थापित की जा रही है । इस कड़ी में नगर में राणा पूंजा भील की मूर्ति स्थापना हेतु भूमि पूजन किया गया। बिरसा मुंडा, एवं परसुराम जी के शस्त्र फरसे की स्थापना हो चुकी है। जबकि जल्द ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी जल्द होने वाला है। पेटलावद-रायपुरिया मार्ग पर लगे डिवाइडर पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी जल्द लगाई जानी है जिसके लिए जगह चिन्हित कर ,भूमि पूजन किया गया इस दौरान उपस्थित आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज डामोर, कोषाध्यक्ष अमर सिंह देवड़ा(नेताजी) जयस जिला संयोजक प्रेम भूरिया जी एवं जयस ब्लॉक अध्यक्ष अमरसिंह देवड़ा, ब्लॉक प्रभारी दिनेश गरवाल, उपा अध्यक्ष भागीरथ कटारा, कोषाध्यक्ष सोहन गरवाल, राजू कटारा, शांतिलाल कतीजा, जगदीश, परवेश सिंगाड़, एवं वरिष्ठ जन सामाजिक कार्यकर्ता, कैलाश वसुनिया सर, पवन खराड़ी, दीपक ताड़ आदि मौजूद रहे।

मनाया अन्नकूट महोत्सव

माही की गूंज, काकनवानी।

प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री सिद्धेश्वर महादेव पर अन्नकूट महोत्सव मनायागया। यह अन्नकूट महोत्सव प्रतिवर्ष दीपावली के चार दिन पश्चात लाभ पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन काकनवानी एवं आसपास क्षेत्र के छोटे-बड़े सभी गांव व पूरे पलवाड़ क्षेत्र से राम भक्त आते हैं और श्री सिद्धेश्वर महादेव पर आकर अन्नकूट का महाभोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

श्री राम बाबा के सानिध्य में भगवान को छप्पन भोग एवं महाप्रसादी का मालपुआ सब्जी, पूरी, दाल, चावल का भोग लगाया। भोग के पश्चात शाम 6 बजे महा आरती की गई इसके बाद महाभोग का भंडारा शुरू किया गया।

एमपी में ही परिवहन होने वाली अवैध शराब को भी गुजरात में परिवहन होना बताकर की जा रही कार्रवाई की इतिश्री

मामलाः खातेगांव में खाकी के कुचल जाने से हुई मौत के बाद भी करवाई महज गोलमोल

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

पुलिस व आबकारी द्वारा वाहनों में पकड़ी जाने वाली सभी शराब गुजरात ही जाती है यह सही नहीं है। गुजरात में झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले से होकर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शराब जाती है इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन पकड़ी जाने वाले प्रत्येक शराब गुजरात ही जाती है यह इसलिए सही नहीं है कि, झाबुआ और आलीराजपुर जिला गुजरात से सट्टा होकर झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले में अनगिनत कुकुरमुत्तों की तरह शराब के अवैध विक्रेता है और जिले व क्षेत्र के ठेकेदार से अवैध शराब लेने के साथ बाहरी शराब भी जो कि सस्ती मूल्य पर इन्हें मिलती है जो लाते हैं। वही ठेकेदारी भी बिना परमिट की अवैध शराब ट्रकों में लोड कर लाते हैं और वैध शराब की तर्ज पर वैध शराब दुकानों या शराब अंडों पर शराब खाली कर जिले व गुजरात तक यह अवैध शराब भी शराब ठेकेदार के माध्यम से खपाई जाती है।

उक्त अवैध एजेंट एवं ठेकेदार की यह परिवहन होने वाली अवैध शराब भी झाबुआ-आलीराजपुर के साथ अन्य जिलो खातेगाव की तर्ज पर शराब जप्ती की कार्रवाईया होती है। लेकिन उक्त मध्यप्रदेश में ही परिवहन होने वाली अवैध शराब को भी गुजरात में परिवहन होना बताकर कार्य की इतिश्री कर दी जाती है।

हमने पूर्व में भी कई बार खुलासा किया कि, शराब कहां से आ रही कहां जा रही तथा उक्त शराब आने-जाने में कौन-कौन लोग शामिल है सभी बेंच नंबर के आधार पर शराब आने का पता लगाया जा सकता है। कई शराब की अवैध गाड़ियां डिपो से नहीं लाकर सीधे फैक्ट्री से जहां आबकारी अधिकारी की निगरानी में ही अवैध शराब निकाली जाती है उन तक अगर कार्रवाई होती तो मुख्यमंत्री को यह घोषणा नहीं करना पड़ती कि, अवैध शराब एवं माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री भी चाहे कितनी ही घोषणा कर दे तो भी ''थोथा चना बाजे घना'' की तर्ज पर ही साबित होगा। क्योंकि शासन के अधीन पुलिस एवं आबकारी के नुमाइंदे चाहे कुछ भी हो जाए तो भी यह माफियाओं को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे। चाहे खातेगांव की तर्ज पर दिलीप पुरी के रूप में खाकी कुचल ही दी जाए तो भी माफिया को संरक्षण देना बंद नहीं होगा। खासकर गुजरात से सेट आदिवासी बाहुल्य झाबुआ-आलीराजपुर जिले में यह धंधा दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा।



एमपी में ही जा रही थी उक्त शराब को भी गुजरात में परिवहन होना बता रही पुलिस।

झाबुआ से बढ़कर आलीराजपुर जिले में ठेकेदार को ही अपनी दादागिरी के साथ अवैध शराब विक्रेताओं का बोलबाला है। वही 1-2 नवंबर की रात्रि में खातेगांव पुलिस ने टिमरनी शराब दुकान से चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) तक ले जाए जा रही शराब के वाहन से पुलिस की कार्रवाई के दौरान टीआई की मौत टायर में कुचल जाने से हो गई। उक्त मौत के बाद भी खाकी अपनी कास्तानी बताने से बाज नहीं आ रही।

खाकी कुचल जाने के बाद मुख्यमंत्री जी मोहन यादव ने माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा घोषणा की। वही यह भी बात सामने आई की जिस टीआई की मौत शराब कार्रवाई के दौरान हुई उसी टीआई पर मनावर में जप्त की गई शराब में से भी आधी जप्ती बताकर आधी शराब बेचने के आरोप विधानसभा में लगाए गए थे। ऐसे में माफियाओं को संरक्षण देने वाली यह वर्दी दागदार ही कहीं जा सकती है। खातेगांव में टीआई की मौत के बाद कार्रवाई का ऐसा नजारा दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब जो भी अवैध शराब पकड़ी जाएगी उसके बाद इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। वही खातेगांव में पुलिस ने कार्रवाई में लाइसेंसी के साथ सिंडिकेट वाले सभी पार्टनर, ट्रक मालिक, चालक, सहचालक सहित ट्रक को मोडिफाइड करने वाले मैकेनिक, सलाहकार और जो भी संबंधित मैनेजर आदि लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान एक आरोपित मोहिन जायसवाल निवासी अहमदाबाद की मौत भी उपचार के दौरान पुलिस की डर से अटैक आने से मौत हो गई। कार्रवाई में टिमरनी ग्रुप की तीनों शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कर जिसका संचालन अब आबकारी विभाग ही कर रहा है। आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को निलंबित के आदेश जारी किए, तो वही शराब दुकान के संचालन करने वाले स्थान कार्यालय पर से उन दस्तावेजों को भी जप्त किया जिसमें ठेकेदार अपनी अपुष्ट कमाई का हिस्सा किस प्रतिशत के अनुसार प्राप्त करते थे। लेकिन उक्त कार्रवाई में भी उक्त जप्त शराब को गुजरात परिवहन होना ही बताया जा रहा है। जबकि माही की गूंज दावे के साथ कहता है कि, ट्रक चालक कैरम सिंह चागोड़ जो कि आजाद नगर थाना क्षेत्र का होकर स्वयं अवैध सप्लायर था। वही आजाद नगर थाना अंतर्गत अवैध शराब बेचने वाले कई विक्रेताओं को केरम सिंह शराब सप्लाई करता था। लेकिन पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही है और यह शराब किस-किस के यहां जा रही थी वह आरोपी नहीं बने है।

इतना ही नहीं अगर पुलिस या आबकारी टिमरनी शराब दुकान संचालन करने वाली ऑफिस पर जाकर दस्तावेजों की जप्ती की बात कर रही है तो प्रतिदिन शराब दुकान पर बनने वाले बिक्री पत्रक को खंगालती तो पता चलता कि, उक्त टिमरनी दुकान से क्षेत्र सहित बाहरी कौन-कौन एजेंट शराब अवैध रूप से ले जाते हैं। और यह एजेंट कब-कब और कितनी कितनी शराब ले गए है। लेकिन बड़ी कार्रवाई का ढकोसला करने वाली पुलिस ने उक्त दस्तावेजों को खंगाल ना उचित नहीं समझा या फिर पुलिस भलीभाती जानती है कि, क्षेत्र सहित बाहरी वह सभी एजेंट अवैध शराब बेचते हैं और उन्हीं से पुलिस व आबकारी को बडा अर्थ लाभ है के चलते उन एजेंटों के यहां कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। तथा जो अवैध शराब आजाद नगर थाना क्षेत्र में ही जाकर खपना थी उस शराब को गुजरात में परिवहन होना बताकर तथा उक्त एक शराब जप्ती पर ही कार्यवाही कर खातेगांव पुलिस अपने कार्य की इतिश्री कर रही है।

संपादकीय

ढह रहे हैं घर लेकिन जवाबदेही तय नहीं



पिछले कुछ समय से दिल्ली में जर्जर इमारतों से होने वाले हादसों में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान असमय चली जाती है। विडंबना यह है कि इन बड़े हादसों के बाद सत्ताधीशों व राजनेताओं की बयानबाजी ही सामने आती है। फिर अगले हादसे तक खामोशी ओढ़ ली जाती है। बड़े-बड़े दावों के बीच 'ट्रिपल इंजन सरकारें' भी जर्जर भवनों के हादसे रोक पाने में असहाय नजर आ रही हैं। इन हादसों के बावजूद निर्माण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने की पहल होती नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों की कोई जवाबदेही भी तय नहीं की जाती। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपराधिक लापरवाही के लिये किसी दोषी को दंडित किया गया हो। साथ ही बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के मामले में भी तंत्र की तरफ से कोई गंभीर कार्रवाई होती नजर नहीं आती। मंगलवार को शाहदरा के ज्वाला नगर में एक इमारत ढह गई, जिसमें एक तीन साल के बच्चे समेत दो लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बना हुई थी। दुखद ही है कि ऐसी दुर्घटनाओं की सूची दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है। सितंबर में तब काफी बवाल मचा था जब सत्य निकेतन की पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। जिसमें पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। तब क्योंकि छात्र आंदोलन का दौर चल रहा था तो छात्रों के गुस्से के मद्देनजर बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद 'वही ढाक के तीन पात' वाली स्थिति सामने आई। बीते अक्तूबर में भी सीमापुरी में जमीन धंसने से चार लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह पांच नवंबर को चावड़ी बाजार हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।

दुखद यह है कि दुर्घटनाओं का यह अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि मई और जुलाई में भी सैदुलजाब और रोहिणी में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। पिछले हफ्ते पहाड़गंज में एक निर्माण स्थल पर छत ढह गई थी। लेकिन गनीमत रही है कि चमत्कारिक रूप से किसी की जान नहीं गई। बहरहाल, बार-बार होने वाली ये त्रासदियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि राजधानी में असुरक्षित इमारतें- अब चाहे वे कॉमर्शियल हों या रिहायशी, पुरानी हों या निर्माणाधीन, अधिकृत हों या अनधिकृत- मौत का जाल बनती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इन हादसों की जवाबदेही तय करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लंबे समय से यह स्थिति बनी हुई है। पुरानी जर्जर इमारतों की अनदेखी, निर्माण के तौर-तरीकों में आपराधिक लापरवाही, सुरक्षा जांच में कमी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते बार-बार लोगों की जान जोखिम में डाला जाना बदस्तूर जारी है। इसमें दो राय नहीं कि यह प्रशासन की विफलता है। विडंबना यह है कि स्थानीय प्रशासन व नगर निकाय घटना के बाद कार्रवाई- मसलन मलबे की जांच करने, चंद अधिकारियों के निलंबन या प्राथमिकी दर्ज करने तक सीमित रह जाता है। वास्तव में होना यह चाहिए कि उन इमारतों को चिन्हित किया जाए, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। ताकि समय रहते कार्रवाई करके लोगों की जान बचायी जा सके। बाद में कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है कि ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति ही न हो। सही मायने में दिल्ली में असुरक्षित व जर्जर इमारतों के सुरक्षा ऑडिट की तत्काल जरूरत है। वास्तव में इन इमारतों की निगरानी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करायी जानी चाहिए। इसी क्रम में जोखिम की स्थिति वाली इमारतों की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के लिये वैकल्पिक आवासों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा जरूरी है कि निर्माण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों,ठेकेदारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। इसके अलावा बिल्डिंग बॉयलॉज के व्यापक उल्लंघन से निपटने के लिये सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है।

अनियंत्रित उपभोक्तावाद से उपजा पर्यावरण संकट



डॉ. ऋतु सारस्वत

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप-31' नामक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच पृथ्वी का औसत सतही तापमान 19वीं सदी के उत्तरार्ध (1850-1900) में दर्ज औसत तापमान की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस रिपोर्ट में तापमान की वृद्धि को समझने के लिए 1850 से 1900 के बीच की अवधि को आधार माना गया है, जिसे जलवायु विज्ञान में पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि कहा जाता है। वहीं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा जारी 'विदाउट रैपिड एक्शन, द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टू इर्रिकवरेबल ओवरशूट' नामक रिपोर्ट में भी वैश्विक जलवायु प्रयासों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को रोकने के सामूहिक वैश्विक प्रयास लगातार पांचवें वर्ष लगभग ठहर गए हैं। वर्तमान सरकारी नीतियों के आधार पर इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन का संकट अब भविष्य की कोई आशंका भर नहीं रह गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घट रही घटनाएं इस संकट की बढ़ती गंभीरता का संकेत दे रही हैं। जुलाई, 2019 में पश्चिमी यूरोप के कई देशों को अविश्वसनीय रूप से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बेल्जियम और नीदरलैंड में तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फ्रांस में जुलाई की भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और कई लोगों की मौत का कारण बनी। वहीं, अप्रैल और मई, 2024 में दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में हुई मूसलाधार बारिश ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।

इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' के निष्कर्ष बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन ऐसी भीषण गर्मी और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की संभावना तथा तीव्रता को बढ़ा रहा है। मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस तथ्य को जलवायु वैज्ञानिक अपने विभिन्न अध्ययनों में लगातार रेखांकित कर रहे हैं। आईपीसीसी की 'जलवायु परिवर्तन 2023 रिपोर्ट' में ऊर्जा के बेतहाशा उपयोग, वनों की निरंतर कटाई और औद्योगिक उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों के रूप में रेखांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल सरकारों और नीतिगत व्यवस्थाओं पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। दरअसल, हमारी अपनी गतिविधियां और दैनिक जीवन से जुड़े निर्णय भी इस समस्या को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसलिए हमें उन गतिविधियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, जिनमें बदलाव करना हमारे अपने हाथ में है।

हमारी इस जिम्मेदारी और व्यक्तिगत भूमिका को समझने के लिए मायरा जे. हर्ड द्वारा संपादित पुस्तक 'कंज्यूमिंग द एनवायरनमेंट' एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दरअसल, हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, फैशन के बदलते चलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग का संबंध केवल बाजार और हमारी जरूरतों से नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ता है। किसी वस्तु का पर्यावरण पर प्रभाव केवल उसके उपयोग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों के दोहन से शुरू होकर उसके उपयोग के बाद फेंक दिए जाने तक बना रहता है। पर्यावरणीय संकट पर विचार करते समय यह देखना भी जरूरी है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं और उन वस्तुओं का उपयोग कितने समय तक कर रहे हैं।



मायरा ने उपभोक्तावाद और पर्यावरण के बीच जिस संबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्तूबर, 2025 की रिपोर्ट 'ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री - एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन रिसोर्स यूज' से भी होती है। रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा उद्योग में हर वर्ष प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग लगभग 8.6 करोड़ ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों में समा सकने वाले पानी के बराबर है। यह उद्योग दुनिया में धरती का तापमान बढ़ाने वाली गैसों के कुल उत्सर्जन में लगभग 8 प्रतिशत योगदान देता है। कपड़ों की बढ़ती मांग और उनके उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर इस दबाव को और बढ़ा रही है।

उपभोक्तावाद का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी-बड़ी वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर तक, प्रत्येक वस्तु के निर्माण और उपयोग के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक लंबी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। एनी लियोनार्ड ने अपनी पुस्तक 'द स्टोरी ऑफ स्टफ' में हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं और पर्यावरण के बीच इसी गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। वे लिखती हैं कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनकी यात्रा धरती से प्राकृतिक संसाधनों को निकालने से शुरू होती है। इसके बाद उनका निर्माण होता है, उन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है, हम उन्हें खरीदते और इस्तेमाल करते हैं और अंततः वे फेंक दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है और पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है।

एनी चेतावनी देती हैं कि वस्तुओं को जल्दी-जल्दी बदलने और नई वस्तुएं खरीदते रहने की प्रवृत्ति केवल हमारी खरीदारी की आदत नहीं, बल्कि ऐसी उपभोग संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव को लगातार गहरा करती है। तो क्या विकास और बेहतर जीवन की हमारी आकांक्षा का अर्थ लगातार अधिक वस्तुएं जुटाते जाना ही है? क्या प्रकृति के संरक्षण के लिए हम अपनी आवश्यकताओं और उपभोग की आदतों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते?

वास्तव में, प्रकृति को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास यह भी है कि हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखें। उपभोक्तावादी संस्कृति की अंधी दौड़ पर लगाम लगाना और अनावश्यक उपभोग से स्वयं को दूर रखना पर्यावरणीय संकट को कम करने की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है। दुनिया के कुछ समाजों में विकसित न्यूनतम वस्तुओं के साथ जीवन जीने की जीवनशैली इसी विचार को व्यवहार में उतारने का मार्ग दिखाती है।

जापान की न्यूनतमवाद की जीवनशैली इस विचार को व्यवहार में उतारने का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। जापानी लेखक फुमियो सासाकी ने अपनी पुस्तक 'गुडबाय, थिंग्स - द न्यू जापानी मिनिमलिज्म' में कम वस्तुओं के साथ संतोषपूर्ण जीवन जीने की सोच को सामने रखा है। इस जीवनशैली का आग्रह है कि हम केवल आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं खरीदें, उनका लंबे समय तक उपयोग करें और केवल नया होने या बाजार में प्रचलित होने के कारण पुरानी वस्तुओं को न बदलें। यह सोच पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आयरलैंड में शुरू हुआ 'लेस बाइंग, मोर बीइंग' का संदेश आज पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन-दृष्टि बन सकता है। कम खरीदना, कम उपभोग करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना केवल पर्यावरण संरक्षण का मंत्र नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। यदि हमने अपनी असीमित इच्छाओं और उपभोग की प्रवृत्ति पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया, तो इसकी कीमत केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। उन्हें उस पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बीच जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ सकता है, जिसकी पीड़ा आज हमारी कल्पना से भी परे है।

शीतकालीन चारधाम यात्रा की भी हैं संभावनाएं

बैकुंठधाम बदरीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड हिमालय की इस वर्ष की चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया। इस यात्रा में लगभग 65 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा की। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन इसके साथ ही इन आराध्य देवताओं के शीतकालीन गद्दीस्थलों में पूजा-अर्चना शुरू हो जाती है।

परंपरा के अनुसार, गंगा की उत्सव डोली शीतकाल में उत्तरकाशी जिले के मुखबा गांव स्थित गंगा मंदिर में विराजमान होती है। यमुना की पूजा खरसाली गांव में होती है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचती है, जहां अगले छह महीने तक उनकी पूजा-अर्चना होती है। इसी प्रकार, बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान उद्धव की पूजा पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी मंदिर में तथा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और भगवान नृसिंह की पूजा ज्योतिर्मठ स्थित नृसिंह मंदिर में होती है।

भौगोलिक विषमताओं और यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद इन हिमालयी तीर्थों के प्रति देश-विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा से होने वाली अधिकांश आय अप्रैल से नवंबर के बीच अर्जित होती है, लेकिन मुख्य धामों के कपाट बंद होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। ऐसे में शीतकालीन गद्दीस्थलों को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्रों के रूप में विकसित करना महत्वपूर्ण पहल है। मुखबा, खरसाली, ऊखीमठ, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ को बेहतर सड़क संपर्क, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार सुविधाओं से जोड़कर वर्षभर के पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे स्थानीय होमस्टे, हस्तशिल्प, पारंपरिक खानपान और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, शीतकाल में भी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।



हालांकि, शीतकालीन चारधाम यात्रा की संभावनाएं आकर्षक हैं, लेकिन इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन गद्दीस्थलों को तीर्थाटन के नए केंद्र बनाने की योजना है, वे भी हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं। सर्दियों में यहां भारी हिमपात, पाला, शीतलहर और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। मुखबा और खरसाली जैसे गांवों में भारी बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क अक्सर बाधित हो जाता है। पांडुकेश्वर और जोशीमठ के आसपास भी हिमपात से यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऊखीमठ अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होने के बावजूद कड़ाके की ठंड और पाले से अछूता नहीं है। इसलिए यह मानना उचित नहीं होगा कि मुख्य धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन गद्दीस्थलों तक पहुंचना हमेशा आसान रहेगा।

सरकार को शीतकालीन गद्दीस्थलों तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर स्नो कटर मशीनों की स्थायी अथवा रणनीतिक तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए। केवल जिला मुख्यालयों पर मशीनें उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। अधिक हिमपात वाले संवेदनशील स्थानों पर पहले से मशीनें, प्रशिक्षित ऑपरेटर और पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होना चाहिए, ताकि बर्फबारी रुकते ही सड़कें खोलने का काम शुरू किया जा सके।

लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है। वैकल्पिक मार्गों की पहचान और आपातकालीन यातायात प्रबंधन की योजना पहले से तैयार रहनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह सतर्क रखना होगा। प्रमुख पड़ावों पर रेस्क्यू पोस्ट, प्रशिक्षित बचावकर्मी, संचार उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार सामग्री और गर्म कपड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में मौसम और बर्फ की स्थिति की लगातार निगरानी हो तथा जरूरत पड़ने पर यात्रियों की आवाजाही तत्काल रोकने की व्यवस्था हो। गद्दीस्थलों पर 24 घंटे चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस, गर्म पानी, हीटिंग और सुरक्षित आवास की सुविधाएं भी जरूरी हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

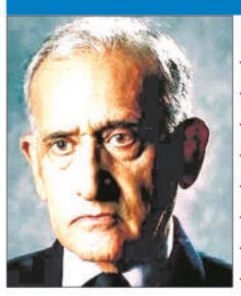


जयसिंह रावत

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ हिमालयी पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील इस क्षेत्र में यात्रियों की संख्या का प्रबंधन, मौसम के अनुसार यात्रा संचालन, कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। प्रतिकूल मौसम में यात्रा को नियंत्रित करने और यात्रियों को समय रहते सूचना देने की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

देवभूमि में आस्था के द्वार कभी बंद नहीं होते। कपाट केवल स्थान बदलते हैं, आराध्य नहीं। मौसम बदलता है, श्रद्धा नहीं। हिमालय की चोटियों से लेकर उसकी तलहटी में बसे शीतकालीन गद्दीस्थलों तक सनातन आस्था की यह धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है।

अग्निपथ योजना में बदलाव का सही समय



एडमिरल अरूण प्रकाश

लागू होने के चार साल बाद, अग्निपथ योजना के समक्ष पहली बड़ी चुनौती बनी, और सरकार ने चुपचाप नीति में बदलाव कर दिया। गत 4 नवंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल के विस्तार को मंजूरी दे दी। चार साल का अनुबंध पूरा होने के बाद, जो अग्निवीर योग्यता के आधार पर शीर्ष 25 फीसदी में नहीं आ पाएंगे, उन्हें बतौर नियमित सैनिक शामिल होने का एक और मौका मिलेगा। अगर तो यह वास्तव में योजना को वापस लेने की शुरुआत है, तो स्वागतयोग्य है। लेकिन चार साल बाद ऐसा बदलाव होने पर वह सवाल उठता है जिसका उत्तर 2022 में कभी सही नहीं दिया गया था - सर्वप्रथम, एक समयसिद्ध, सफल व अच्छी तरह स्थापित प्रणाली इतनी जल्दबाजी में क्यों बदली जा रही है?

14 जून, 2022 को प्रेस सूचना ब्यूरो के एक नोट में कहा गया कि इस योजना से 'सशस्त्र बलों का चेहरा युवा रहेगा', 'नया जोश और जज्बा भरेगा' व सेना 'और अधिक तकनीक-कुशल' बनेगी। इसमें देशभक्ति, टीमवर्क, शारीरिक फिटनेस व देश के प्रति निष्ठा जैसे लाभों का भी जिक्र किया गया था।

उक्त 'तर्कों' में से एक भी भर्ती की एक स्थापित प्रणाली, बुनियादी प्रशिक्षण व सैनिकों को चरणबद्ध रूप से शामिल करने की व्यवस्था को ध्वस्त करके, उसकी जगह एक ऐसी योजना लाने को न्यायोचित नहीं ठहराती, जिसे पहले कभी आजमाया नहीं हो और जो मूलतः त्रुटिपूर्ण है। जिन्होंने भर्ती रैलियां देखी हैं या उनके बारे सुना है, वे जानते हैं कि हमारे देश के युवाओं में जोश-जज्बे की कोई कमी नहीं; वे हजारों की संख्या में सेना में शामिल होने आते हैं। हमारी रेजिमेंटों, युद्धपोतों और स्क्वाड्रनों में नियुक्त फौजियों में देशभक्ति, टीमवर्क और फिटनेस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। साथ ही, 'देश के प्रति वफादारी' पैदा करने का तर्क इतना भी मजबूत नहीं कि इसके लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए, जो दीर्घकाल में सशस्त्र बलों के मूल ढांचे पर ही असर डाल दे।

भर्ती की औसत उम्र की घटाना एक अच्छा लक्ष्य लग सकता है, लेकिन उम्र का सीधा संबंध युद्ध लड़ने की क्षमता से नहीं होता। यह क्षमता कौशल से बनती है, और कौशल हासिल करने में समय लगता है। ज्यादातर देहात से आने वाले और हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली से निकले नए रंगरूटों के लिए चार से छह महीने का बुनियादी प्रशिक्षण नाकाफी है। किसी सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को जटिल और महंगे युद्धक उपकरण या हथियार सौंपना या उसको असल युद्ध जैसी स्थितियों में उतारने से पहले, दो-तीन साल का व्यावहारिक एवं काम के दौरान अनुभव पाने हेतु प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

हो सकता है कि कोई नया रंगरूट स्मार्टफोन चलाने में माहिर हो, लेकिन रडार, फायर-कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, एयरो-इंजन या साधारण डीजल जनरेटर कैसे काम करते हैं, यह समझने और एक कुशल 'ऑपरेटर' बनने की महारत के लिए उसे महीनों प्रशिक्षण की जरूरत होगी। ऑपरेटरों के साथ 'मेंटेनर' होते हैं, जो इन प्रणालियों की सर्विसिंग करते हैं और खराबियां ठीक करते हैं। इन्हें प्रशिक्षित होने में और ज्यादा समय लगता है। इन सबके ऊपर 'उस्ताद' होते हैं, जिनका दशकों का अनुभव होता है और ये उस्ताद अधिकारियों सहित सबको सिखाते हैं। साढ़े सत्रह साल की उम्र में भर्ती होने वाले हर सैनिक को सिखाने के लिए, सेनाओं को अनुभवी और युद्ध से तपे सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर की जरूरत होती है, जो 54-56 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगर आप इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं न कहीं कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसका उदाहरण नौसेना में देखने को मिला, जिसने 2022 में अपना 'आर्टिफिसर कैडर' खो दिया, वह इकाई जो नौसेना के हथियार, सेंसर और मशीनरी के रखरखाव की आपूर्तिकर्ता होती है।

अग्निपथ योजना के तहत, चार साल के कार्यकाल में से अगर बुनियादी प्रशिक्षण, वार्षिक छुट्टी और सेवामुक्त होने से पहले की अवधि घटा दें, तो एक सैनिक की वास्तविक उपलब्धता लगभग तीन साल ही बचती है। इससे कुछ परेशानीकारक सवाल उठते हैं- क्या सेना ऐसे व्यक्ति को तकनीकी स्किल सिखाने में निवेश करना चाहेगी,जिसकी नौकरी जल्द ही खत्म होने वाली हो? क्या अग्निवीर खुद भी इन कौशलों को सीखने में दिलचस्पी लेगा, जब उसका आगे बने रहना ही पक्का न हो? योजना के तथाकथित लाभ दोनों ही पक्षों के लिए गलत दिशा की ओर इंगित करते हैं। चाहे यह विचार सेना मुख्यालय से आया हो या रक्षा मंत्रालय ने थोपा हो, इतने बड़े बदलाव को पहले एक 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में आजमाना चाहिए था—यानी इसे किसी एक या अधिक सैन्य यूनिटों में प्रयोग किया जाता, या बेहतर होगा कि 'टेरिटोरियल आर्मी' में लागू कर देखा जाता और फिर परिणामों का विश्लेषण किया जाता। इसके बजाय, पूरी सशस्त्र सेना पर अचानक इस जोखिम भरे प्रयोग को लाद दिया गया।

हालांकि सरकार लगातार यह कहती रही है कि इसके पीछे कोई वित्तीय मकसद नहीं, लेकिन लगभग तय है कि अग्निवीर योजना रक्षा मंत्रालय के बढ़ते 'कार्मिक खर्चे' को नियंत्रित करने से चालित है, क्योंकि सब खर्चों के बाद,हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध फंड में कमी आ जाती है। तथापि, पेंशन खर्च मद में बचत किए जाने की एवज में रक्षा क्षमताओं से समझौता करना बहुत बुरा सौदा है। अगर बचत इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, तब तो इस योजना का सबसे ठोस आधार ही खत्म हो जाता है।

केंद्र सरकार की पेंशन प्रणाली के लाभार्थी केवल पूर्व सैनिक ही नहीं हैं। सिविल नौकरशाही का पेंशन खर्च भी उसी दर से बढ़ रहा है, फिर भी कोई यह सुझाव नहीं देता कि उनके कार्यकाल को घटा कर, साल में दो बार मिलने वाले महंगाई भत्ते को रोककर, या 8वें वेतन आयोग को टालकर पैसे की समस्या को सुलझाया जाए।

अपनी 1999 की किताब 'डिफेंडिंग इंडिया' में, पूर्व भाजपा मंत्री और सेना (बख्तरबंद फौज) के सेवानिवृत्त मेजर जसवंत सिंह ने लिखा था कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकारी खजाने पर पहली लागत माना जाता है'। उन्होंने चेताया था कि पेंशन का भुगतान, वेतन एवं भत्तों की तुलना में तिगुणी तेजी से बढ़ रहा है- एक ऐसी समस्या जिसका सामना देश को एक दिन करना ही पड़ेगा। तेईस साल बाद, अग्निपथ को एक 'रामबाण' के रूप में पेश किया गया—एक वित्तीय समाधान, जिसे 'सैन्य सुधार' का नाम देकर थोपा गया। बीते कुछ सालों से, ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें सशस्त्र सेनाओं को कतिपय राजनीतिक आदेशों या अदालती फैसलों



को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनके मूल सिद्धांतों और युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सैन्य नेतृत्व को दृढ़ता रखनी चाहिए और स्पष्ट संदेश दे - कोई भी प्रस्तावित सुधार या बदलाव अनिवार्यतः इस कसौटी पर खरा उतरता हो- क्या इससे युद्ध क्षमता बढ़ेगी है या घटेगी? अग्निपथ योजना इस कसौटी पर विफल रहती है - यह अनिवार्य प्रशिक्षण को प्रभावित करती है, सैनिकों के बीच अलग-अलग श्रेणियां पैदा कर, यूनिट के भीतर आपसी जुड़ाव को भंग करती है, और उन सैनिकों का मनोबल गिराती है, जिन्हें ऐसी शर्तों के तहत अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहा जाए, जो साथी सैनिकों पर लागू नहीं होतीं।

दो साल का विस्तार शायद एक कठिन फैसले को टालकर कुछ वक्त की राहत दे दे, लेकिन यह उपाय चीज़ें सुलझाने की बजाय और अधिक समस्याएं पैदा करता है और सेना को दुविधा में डालता है। अगर सरकार अब मान रही है कि ऑपरेशनल जरूरतों के लिए प्रशिक्षित जवानों को सेवा में बनाए रखना जरूरी है, तो उसे पर्याप्त प्रशिक्षण आधारित पुराना भर्ती मॉडल फिर से लागू करना चाहिए, 'कलर सर्विस' (सक्रिय सेवा) की एक न्यूनतम अवधि तय हो, और किसी भी भावी सैन्य सुधार का मूल्यांकन सिर्फ 'युद्ध क्षमता' के आधार पर किया जाए। अग्निपथ योजना में पैबंद लगाकर सुधार करके काम नहीं चलने वाला; इसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए।

एसपी ऑफिस टेंडर मामले में केस दर्ज

माही की गूंज, शाजापुर।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर के स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री टेंडर हासिल करने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना प्रिंटिंग प्रेस संचालक को भारी पड़ गया। मामले में थाना लालघाटी पुलिस ने नवीन प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर मोहम्मद अली के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह काफी चर्चित मामला है।

प्रिंटिंग प्रेस संचालक को कार्रवाई से बचाने के नाम तत्कालीन एसपी के नाम से एसपी बंगले के बाहर 25 लाख रुपये के लेनदेन की शिकायत भी सामने आई थी। शिकायत की जद में पुलिस अधिकारी और जवान भी आ रहे थे, इसलिय उसे जांच के नाम पर दबा दिया गया। बहरहाल कूट रचित दस्तावेज लगाकर टेंडर हासिल करने को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में लालघाटी थाना पुलिस जांच कर रही है।

एडिट कर दस्तावेज दोबारा प्रस्तुत किए

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई सड़क निवासी अंकित नागर (प्रोपराइटर अंकित ट्रेडर्स) ने 27 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की खरीदी के लिए जारी निविदा में नवीन प्रिंटिंग प्रेस शाजापुर के संचालक मोहम्मद अली द्वारा पिछले तीन वर्षों से कथित रूप से फर्जी दस्तावेज लगाए जा रहे हैं। आरोप था कि निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ पत्र एवं गुमास्ता पंजीयन में दर्ज तारीखों को एडिट कर दस्तावेज दोबारा प्रस्तुत किए गए। शिकायत की जांच के दौरान आवेदक अंकित नागर एवं अनावेदक मोहम्मद अली के बयान दर्ज किए गए। मोहम्मद अली ने अपने बयान में बताया कि अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की निविदा में गुमास्ता पंजीयन एवं शपथ पत्र लगाए गए थे, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से गलत तारीख दर्ज हो गई थी।



इस त्रुटि के कारण विभाग द्वारा उनका टेंडर अपात्र कर दिया गया था। हालांकि पुलिस जांच में कूटरचना करना सामने आया। जांच प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर मोहम्मद अली पिता तैय्यब अली, उम्र 47 वर्षए निवासी दरगाह रोड गिरवर, शाजापुर, प्रोपराइटर नवीन प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आई सच्चाई

जांच में नोटरी अधिवक्ता प्रहलादचंद्र सिंदल के बयान भी दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली ने 15 अप्रैल 2025 को एक शपथ पत्र नोटरी सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया था, जिसे उनके नोटरी रजिस्टर में क्रमांक 2398 पर दर्ज कर प्रमाणित किया गया था। अधिवक्ता ने 13 अप्रैल 2026 को मोहम्मद अली का कोई शपथ पत्र नोटरी सत्यापित करने से इंकार किया।

इसके बाद नोटरी रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति भी जांच में प्राप्त की गई। वहीं, श्रम विभाग शाजापुर से गुमास्ता पंजीयन की ऑनलाइन प्रति प्राप्त कर निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान किया गया। जांच में गुमास्ता पंजीयन में भी तारीख के साथ एडिटिंग किए जाने की बात सामने आई।

तत्कालीन एसपी के नाम से 25 लाख की कथित अवैध वसूली, नहीं हुई कार्रवाई

पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज लगाकर निविदा हासिल करने के मामले में प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज कर लिया है। किंतु इसी मामले को दबाने के नाम पर हुए कथित 25 लाख रुपए के अवैध लेनदेन। पुलिस अधिकारियों व कोतवाली थाना पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर फिलहाल कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि जिस मामले में नवीन प्रिंटिंग प्रेस के संचालक पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी। जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने छह माह तक दबाए रखा।

मामले में कार्रवाई से बचाने के नाम पर एसपी बंगले के बाहर तत्कालीन एसपी के नाम से 25 लाख रुपए का अवैध लेनदेन होने की शिकायत सामने आई थी। जिसे पुलिस अधिकारियों और महकमें की छवि धूमिल हुई है। हालांकि इतने सब के बावजूद अब तक इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी या कोतवाली थाने के जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामले में आवेदन की जांचकर्ता से लेकर थाना टीआइ की भूमिका संदिग्ध है।

हिस्ट्रीशीटर वसीम खान की 1.25 करोड़ की संपत्ति फ्रीज...

माही की गूंज, मंदसौर।



मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अरनोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्रीशीटर वसीम खान की लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है। पुलिसकर्मियों ने आरोपित के आलीशान मकान सहित अन्य पर बोर्ड लगाकर कब्जे में लेने की कार्रवाई की। फ्रीज की गई संपत्ति में आलीशान मकान, क्रेटा कार और जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर भी शामिल है। आरोपित पर मप्र व राजस्थान में कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

सफेमा कोर्ट की मंजूरी के बाद संपत्तियों पर लगाए बोर्ड

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि वसीम खान निवासी देवगढ़ी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी में लिप्त है। उसके खिलाफ वर्ष 2003 से 2026 तक राजस्थान और मप्र में हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी सहित कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

इसकी संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर सफेमा कोर्ट भेजा गया था। सक्षम प्राधिकरण ने 13 नवंबर को फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी देकर स्थायी किया। इसके बाद रविवार को पुलिस ने संबंधित संपत्तियों पर बोर्ड लगा दिए।

जोधपुर में पकड़ी गई एमडी और स्मैक की खेप में सामने आया था नाम

1 अप्रैल 2026 को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना पुलिस ने आरोपित समंदर निवासी हिंगोली से 80.54 ग्राम एमडी और 1.25 ग्राम स्मैक जब्त कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच में समंदर ने बताया कि मादक पदार्थ वसीम खान ने उपलब्ध कराए थे। इसके बाद वसीम खान को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अभी वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

ये तीन संपत्तियां फ्रीज

पुलिस के अनुसार वसीम खान ने मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए रुपयों से देवगढ़ी गांव में आबादी भूमि पर आलीशान मकान, टीन शेड और जमीन खरीदी थी। इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा कार (एमपी 09 सीवाई 9495) और ट्रैक्टर को भी फ्रीज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया के लिए 16 अक्टूबर को सफेमा कोर्ट प्रस्ताव भेजा गया था। सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी दी।

चंबल सफारी में मंत्रियों संग घूमे सीएम

माही की गूंज, गांधी सागर।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार सुबह कैबिनेट बैठक से पूर्व मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गांधी सागर अभयारण्य में चंबल सफारी का आनंद लिया। प्रकृति की गोद में बसे इस मनोरम क्षेत्र में आयोजित सफारी में यात्रा सीएम ने राज्य सरकार की पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही।

बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उनके कैबिनेट मंत्री टेंट सिटी से चंबल नदी पर बने गांधीसागर जलाशय से तटीय क्षेत्रों और घने जंगलों की ओर निकले। सफारी के दौरान मंत्रियों ने क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता, दुर्लभ वन्यजीवों और चंबल के शांत व आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों का करीब से अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय वन अधिकारियों से अभयारण्य में चल रहे विकास कार्यों, चीतों के पुनर्वास की तैयारियों और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की।

इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर और चंबल का यह क्षेत्र अपार पर्यटन संभावनाओं से भरा हुआ है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे अनछुए प्राकृतिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करना है। इससे न केवल इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस अनौपचारिक भ्रमण ने मंत्रियों के बीच आपसी संवाद और टीम भावना को भी मजबूत किया। सफारी के उपरांत मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुआ।

पांच इको टूरिज्म परियोजनाओं, पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांधीसागर में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के निवेश संवर्धन अंतर्गत 40.50 करोड़ रुपये में विकसित होने वाली 5 ईको टूरिज्म परियोजनाओं एवं पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन किया।इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गांधीसागर में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी।

इस आधुनिक तकनीक से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 20 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दो जलाशयों के बीच पानी का बार-बार उपयोग कर बिजली बनाई जाएगी, जिससे पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव संपदा और पर्यटन की अपार संभावनाओं से समृद्ध है।

यहां विकसित हो रही टेंट सिटी पर्यटन को नई पहचान देगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट के आयोजन से क्षेत्र में विकास, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने परियोजना को देश के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण और भविष्य में केस स्टडी बताया।

13 दिन में एक विकेट उड़ेगा

माही की गूंज, रतलाम। सरकारी वॉट्सएप ग्रुप में चुनौती भरे और धमकी भरे संदेश पोस्ट करना पिपलौदा तहसील में पदस्थ सहायक वर्ग 3 कर्मचारी पुष्पेंद्र बॉस को भारी पड़ गया। कार्यालयीन संवाद की मर्यादा तोड़ने और सरकारी सेवा की गरिमा के प्रतिकूल संदेश प्रसारित करने के आरोप में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने इस मामले को अनुशासनहीनता, कदाचरण और घोर लापरवाही की श्रेणी में माना है।

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, पुष्पेंद्र बॉस ने आधिकारिक वॉट्सएप ग्रुप में अलग-अलग समय पर ऐसे संदेश पोस्ट किए, जिनकी भाषा उत्तेजक, चुनौतीपूर्ण और धमकी भरी थी। संदेशों में उन्होंने लिखा, 'अंतिम अब प्रहार है, युद्ध आर-पार है... मैं भी पुष्पेंद्र बोस हूं... बाहर का व्यक्ति यहां राज करने की कोशिश करेगा... नौकरी रहेगी तो विरोध संभव है, वरना जय हिंद, जय भारत।'

तो मैं धमाके शुरू करूंगा

एक अन्य संदेश में उन्होंने लिखा, 'तुम्हारी दिवाली अगर खत्म हो गई है तो मैं धमाके शुरू करूंगा। 13 दिन में एक विकेट उड़ेगा... जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, खुला चैलेंज।' सरकारी कार्यालय के आधिकारिक संवाद समूह में इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। कर्मचारी के इन संदेशों को शासकीय सेवा की मर्यादा और आचरण के विपरीत माना गया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के नियम 3:1(प) के अनुरूप नहीं पाया गया। उनके कृत्य को अनुशासनहीनता और कदाचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जांच के दौरान सहकर्मियों पर तनाव की आशंका

प्रशासनिक दृष्टि से विभागीय जांच के दौरान कर्मचारी को वर्तमान कार्यस्थल से अलग रखना आवश्यक माना गया है, ताकि कार्यालयीन वातावरण प्रभावित न हो और सहकर्मियों पर किसी तरह का तनाव न रहे। निलंबन अवधि में पुष्पेंद्र बॉस का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, रतलाम निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शादी का बचा खाना खाने से 5 गायों की मौत, 16 बीमार

माही की गूंज, शाजापुर/नलखेड़ा।

नगर में शादी समारोह के बाद बचे भोजन को खुले में फेंकना गोवंश के लिए जानलेवा साबित हुआ। बताया जा रहा है कि यह भोजन खाने से पांच गायों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गोवंश बीमार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिवाजी चौराहे पर धरना दिया और नलखेड़ा थाने में शिकायत की।

उपचार के दौरान पांच गायों ने तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, नगर निवासी अयान पुत्र अली हुसैन लखेरा के यहां शादी समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में मेहमानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार किया गया था। आरोप है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बचे भोजन का उचित निस्तारण करने के बजाय उसे खुले स्थान पर फेंक दिया गया। इसे खाने के बाद गोवंश की तबीयत बिगड़ने लगी। गायों की हालत खराब होते देख स्थानीय लोगों ने पशु चिकित्सकों को सूचना दी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

डॉ. संदीप नागर के नेतृत्व में पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और बीमार गोवंश का उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान पांच गायों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य की हालत नाजुक बताई जा रही है। धरना-प्रदर्शन और शिकायत के बाद पुलिस ने अली हुसैन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिंदू संगठनों ने दिया धरना

घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौराहे पर धरना दिया। उन्होंने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठनों का कहना है कि भोजन के अवशेष खुले में फेंकने से गोवंश की जान पर बन आई और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।



पति-पत्नी के विवाद के बाद महिला की मौत

माही की गूंज, रतलाम।



रावटी थाना क्षेत्र के रानिसिंग गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान और गले पर निशान मिले हैं। आशंका है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। घटना के बाद से पति की तलाश की जा रही है।

रानिसिंग निवासी मांगीलाल पुत्र गेंदालाल गरवाल का मंगलवार रात पत्नी कलाबाई से विवाद हुआ था। बुधवार सुबह करीब 8 बजे मांगीलाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि अंबाराम गरवाल के घर पहुंचा। वे उस समय सो रहे थे। इसके बाद करीब 10 बजे मांगीलाल ने फोन पर सूचना दी कि पत्नी की मौत हो गई है। उसने बताया कि रात में विवाद के बाद वह सो गया था और सुबह उठने पर पत्नी की मौत की जानकारी मिली।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की

गांव के चौकीदार छोटेलाल मालिवाड ने पुलिस को सूचना दी। जांच के लिए एफएसएल अधिकारी डॉण् अतुल मित्तल मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट और गले पर निशान मिले हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि पति की तलाश के लिए टीम लगाई गई है।

परिवार के तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा करण विवाहित हैए जबकि अर्जुन और कमलेश अविवाहित हैं। तीनों गुजरात में मजदूरी करने गए हुए हैं। घटना के समय पति.पत्नी घर पर अकेले थे। सास.ससुर दूसरे मकान में रहते हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है।

वर्षों का संघर्ष रंग लाया

माही की गूंज, रतलाम।

वर्षों तक ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, आलोट-विक्रमगढ़ बंद कराया और रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम के खिलाफ सड़क से अखबार तक आवाज बुलंद की। विक्रमगढ़ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का लंबा संघर्ष अब मुकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के गेट नंबर 21 पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज का 21 नवंबर को भूमि पूजन होगा। सांसद अनिल फिरोजिया इसकी आधारशिला रखेंगे। वर्षों से जाम में फंसने की मजबूरी झेल रहे हजारों लोगों के लिए यह दिन संघर्ष की सफलता की नई शुरुआत बनेगा।

वर्षों से रेलवे फाटक पर ट्रेनों के गुजरने का इंतजार और जाम में फंसे रहने की मजबूरी अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर आलोट अनुभाग के विक्रमगढ़ रेलवे फाटक (गेट नंबर 21) पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठने जा रहा है। 21 नवंबर को सांसद अनिल फिरोजिया ओवरब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना के लिए क्षेत्रवासियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। जनआंदोलनए ज्ञापन और लगातार उठती मांग के बीच राजस्थान पत्रिका ने भी इस जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित किया।



फाटक बंद होते ही थम जाती थी जिंदगी

विक्रमगढ़ रेलवे फाटक पर ट्रेनों की आवाजाही के कारण बार-बार आवागमन बाधित होता था। फाटक बंद होते ही दोनों ओर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं। स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी होती तो नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों का समय जाम में गुजरता था। सबसे गंभीर स्थिति मरीजों को लेकर गुजरने वाले वाहनों की होती थी। कई बार जरूरी काम से निकले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। इस परेशानी का स्थायी समाधान ओवरब्रिज निर्माण को ही माना जा रहा था।

आंदोलन, ज्ञापन और बंद से बुलंद की आवाज

ओवरब्रिज की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों और ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति ने लंबे समय तक संघर्ष किया। ज्ञापन देने से लेकर आंदोलन और आलोट-विक्रमगढ़ बंद तक के कदम उठाए गए। हर स्तर पर जिम्मेदारों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने का प्रयास हुआ। अखबारों ने भी फाटक पर लगने वाले जाम, आमजन की परेशानी और ओवरब्रिज की जरूरत को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित किए। जनहित से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता मिलने के साथ क्षेत्रवासियों की मांग लगातार बुलंद होती रही।

तैयारियों का लिया जायजा, लोगों से की अपील

21 नवंबर को प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रेलवे समिति सदस्य नंदनराज जैन, मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया, संघर्ष समिति के राकेश पोरवाल, भूपेंद्र सिंह सोलंकी, डॉ. देवेंद्र विशाल, राघवेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

अब जाम से मुक्ति की उम्मीद

विक्रमगढ़ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग वर्षों से क्षेत्रवासियों के संघर्ष का विषय रही है। 21 नवंबर को होने वाला भूमि पूजन इस लंबे इंतजार के बाद निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत होगा। ओवरब्रिज बनने से रेलवे फाटक पर बार-बार रुकने की मजबूरी खत्म होगी और क्षेत्र के लोगों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य की गति पर टिकी हैं।

गौरव दिवस कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर विधायक जी नाराज

माही की गूंज, बड़वानी।

सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के चाचरिया पाटी गांव में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम और उसकी तैयारियों को लेकर हुई बैठक में विधायक मोंटू सोलंकी को आमंत्रित नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। विधायक ने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक समर्थकों ने एसडीएम सेंधवा को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। विधायक मोंटू सोलंकी ने आयुक्त, इंदौर संभाग, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, कलेक्टर बड़वानी, सहायक आयुक्त और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव पी.के. सिंह को अलग-अलग पत्र लिखे हैं।



पत्र में विधायक ने कहा कि सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें कार्यक्रम का औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया और न ही पहले से कोई सूचना दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों से संबंधित बैठक में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया।

विधायक ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्यक्रम में एक राजनीतिक दल को महत्व देने जैसी स्थिति बनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का निजी आयोजन नहीं होता। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित अधिकारियों से लिखित जवाब लेने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में शासकीय कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आमंत्रित करना सुनिश्चित करने की बात कही है।

इस दौरान प्रिंस शर्मा, कलम अवाया, विवेक मेहता, सुनील नरगावे, ग्यारसिलाल मोरे और अमरसिंह सोलंकी मौजूद रहे।

स्वामित्व योजना में लापरवाही पर दो पटवारी निलंबित

माही की गूंज, खंडवा।

स्वामित्व योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने खंडवा जिले के दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं होने और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। निलंबित पटवारियों में खालवा तहसील के मनीष राठौर और किल्लौद तहसील के मुकेश मार्को शामिल हैं।

एसडीएम हरसूद रमेश खतेड़िया ने बताया कि स्वामित्व योजना राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना अनिवार्य है। खालवा तहसील के ग्राम डाभिया और पटाल्दा में पदस्थ पटवारी मनीष राठौर को कार्य में तेजी लाने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रगति में सुधार नहीं हुआ। इस पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। लगातार निर्देशों की अनदेखी और जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

इसी प्रकार किल्लौद तहसील के ग्राम जूनापानी और मालूद में पदस्थ पटवारी मुकेश मार्को के विरुद्ध भी स्वामित्व योजना के कार्य में लापरवाही सामने आने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान मनीष राठौर का मुख्यालय तहसील कार्यालय खालवा और मुकेश मार्को का मुख्यालय तहसील कार्यालय किल्लौद निर्धारित किया गया है। इस अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।



भिलट चौक पर लगाए पाइप से रहवासी परेशान

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।



तीर्थ नगरी में एसडीएम के निर्देश पर लगाए गए अवरोधक स्थानीय रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। आम लोगों को हो रही असुविधा के बीच नगर परिषद ने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।

दरअसल, बालवाड़ी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए प्रशासन ने भिलट चौक (गधा चौक) से बालवाड़ी जाने वाले रास्ते पर पाइप लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। इससे दो-तीन वार्डों के रहवासियों, स्कूली बच्चों और आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

बुधवार सुबह स्कूल बसों को बच्चों तक पहुंचने के लिए करीब एक किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ा। पहले बसें सीधे बालवाड़ी पहुंचती थीं, लेकिन अब उन्हें फॉरेस्ट तिराहे से पुराने बस स्टैंड वाले रास्ते से घूमकर जाना पड़ रहा है।

इस व्यवस्था से बच्चों को बस तक छोड़ने और वापस लेने जाने वाले अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ गई है। उन्हें करीब एक किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। रहवासियों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए यह व्यवस्था काफी असुविधाजनक है।

सड़क के बीच पाइप लगाए जाने से एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के आवागमन को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में वैकल्पिक रास्ते से घूमकर जाने में समय लग सकता है।

रहवासियों का कहना है कि पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुचारू रखना नगर परिषद की जिम्मेदारी है। जगह-जगह अवरोधक लगाकर रास्ते सीमित करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने स्कूली बच्चों, स्थानीय रहवासियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए आवागमन का सुगम रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है।

नगर परिषद की सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गधा चौक पर पाइप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को हुई बैठक में एसडीएम पंकज वर्मा ने प्रभारी राजस्व निरीक्षक को गधा चौक पर अवरोधक लगाने और व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इलेक्ट्रिक और मेडिकल स्टोर में लगी आग

माही की गूंज, खरगोन। सनावद रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रिक और एक मेडिकल स्टोर में मंगलवार रात आग लग गई। आग की चपेट में आने से दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है।

घटना जैतापुर थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे हुई। दुकानों से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर नगरपालिका की दो दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को घटनास्थल से दूर किया, ताकि राहत और बचाव कार्य में परेशानी न हो। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

आवास योजना के 14 मकान अधूरे, हितग्राहियों को नोटिस

माही की गूंज, बड़वानी। नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत 14 हितग्राहियों ने अब तक अपने मकानों का निर्माण पूरा नहीं कराया है। इस मामले में नगर पालिका ने संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं, अब शेष राशि की वसूली के लिए तहसीलदार के माध्यम से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।

वर्ष 2016 से 2022 के बीच नगर पालिका क्षेत्र में योजना के तहत 1,909 मकान स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 1,895 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 14 मकान अधूरे हैं या उनका निर्माण शुरू ही नहीं किया गया है। इन अधूरे मकानों के मामले में करीब 14 लाख रुपए की वसूली की जानी है। इसमें से 10 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि शेष 4 लाख रुपए वसूलने के लिए तहसीलदार के माध्यम से नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका के उपयंत्री बलदेव सिंह ठाकुर ने बताया कि अधूरे मकानों वाले हितग्राहियों को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। निर्धारित समय में मकान का निर्माण पूरा नहीं करने पर संबंधित हितग्राहियों से राशि की वसूली की जाएगी। शेष राशि वसूलने के लिए जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पाइपलाइन तोड़कर पानी की आपूर्ति रोकी, दो किसानों पर मामला दर्ज

माही की गूंज, खंडवा।



उद्वहन सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना मुंदवाड़ा गांव की है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से मुंदवाड़ा सहित आगे जुड़े सिहाड़ा गांव के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने में परेशानी हुई।

कार्यपालन यंत्री एसपी तिर्की की शिकायत पर मंगलवार को मोघट रोड थाना क्षेत्र की रामेश्वर पुलिस चौकी में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने ग्राम बड़ियातुला निवासी खालिद पिता अय्यूब और खलील पिता अय्यूब के खिलाफ लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों पर मुंदवाड़ा में परियोजना की एचडीपीई पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है।

पाइपलाइन में टूट-फूट होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे परियोजना पर निर्भर किसानों की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो गई। इसका असर मुंदवाड़ा के साथ सिहाड़ा गांव के किसानों पर भी पड़ा।

जावर उद्वहन सिंचाई परियोजना की एडीएम क्षितिज शर्मा और एसडीएम ऋषि सिंघई लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन में रिसाव, टूट-फूट या अन्य तकनीकी समस्या सामने आने पर तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों तक पानी पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जा रहा है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन सार्वजनिक संपत्ति है और इससे बड़ी संख्या में किसानों की सिंचाई व्यवस्था जुड़ी हुई है। पाइपलाइन से छेड़छाड़ या तोड़फोड़ करने और किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के हितों और सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

प्रदेश में फैल रहा अवैध और जहरीली शराब का कारोबार, मध्यप्रदेश के शराब तस्करों का नेटवर्क गुजरात तक



रिंकेश बैरागी

माही की गूंज, झाबुआ।

हाल ही में देवास जिले में अवैध शराब की तस्करी करने वालों ने मौके पर जांच कर रहे थाना प्रभारी को कुचलते हुए उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ लिया, साथ ही अवैध शराब के कारोबारियों को भी धर दबोचा। वहीं प्रदेश में जहरीली शराब का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि प्रदेश की पुलिस और आबकारी विभाग उसे तोड़ने में पूर्ण रूप से असफल हैं। एक जानकारी के अनुसार प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा है, जहां अवैध शराब का परिवहन और जहरीली शराब की बिक्री न होती हो। यहां तक कि प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में तस्करों का नेटवर्क इतना अधिक मजबूत हो गया है कि प्रदेश से अवैध शराब का कारोबार सीमा पार गुजरात राज्य में भी आसानी से किया जाता है। जबकि गुजरात राज्य भारत देश का एक ऐसा पहला राज्य है, जहां शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्षों पहले बंबई प्रांत से महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य को पृथक किया गया। उसके बाद 1 मई 1960 में गुजरात राज्य में शराब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था, किंतु वर्तमान स्थिति यह है कि गुजरात के हर शहर में शराब मिल जाती है।

शराब प्रतिबंध वाले राज्य में शराब की तस्करी मध्यप्रदेश के जिलों से होती है और तस्करी उन जिलों से की जाती है, जो गुजरात सीमा से सटे हुए हैं। एक सूचना के अनुसार बीते कुछ दिनों पूर्व गुजरात के गोधरा में जो अवैध शराब पकड़ी गई थी, उसमें भाजपा नेता के संबंधी का नाम सामने आया था, लेकिन लेन-देन का खेल खेलते हुए उस नाम को हवा कर दिया गया। एक और मामला, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने सीमा के समीप पहुंचकर अवैध शराब को सीमा के पार पहुंचाया, जबकि उस महिला अधिकारी को उस क्षेत्र से बहुत पहले ही हटा दिया गया था। लेकिन पुरानी पहचान और भाजपा नेता के अति संपर्क में होने के कारण उसने अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर लालच की लार टपकाते हुए अवैध शराब को सीमा के पार करवा दिया। उस महिला अधिकारी का जिले से प्रमोशन भी हो चुका है।

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों पहले मुरैना, सागर और अब देवास जिले में जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी हैं। जिसको लेकर विरोध भी प्रदेश में हो चुका है, मगर सरकार के हाथ से झुनझुना छूट नहीं रहा है। प्रदेश से शराब की गुजरात में तस्करी होने की बात अनेक बार साबित भी हो चुकी है, किंतु सरकार द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश की जनता चाहती है कि अवैध शराब और जहरीली शराब पर सरकार सख्त हो और इन अवैध कारोबारियों को सलाखों के पीछे कर मौत के इस कारोबार को पूर्ण रूप से बंद किया जाए।

गुजरात के भावनगर में भी जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। इसके तार भी मध्यप्रदेश से जुड़े हुए थे। गुजरात पुलिस ने शराब की आपूर्ति में उज्जैन से संबंध जोड़ा था। यहां के तीन लोगों सहित गुजरात में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ अवैध और जहरीली शराब का प्रकरण दर्ज किया था। उज्जैन के बेगमबाग निवासी रईस रफीक अंसारी, बाफना पार्क कॉलोनी निवासी जुबेर और अर्जुन गोहिल के नाम सामने आए थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार रईस रफीक लंबे समय से भावनगर में रह रहा था और घटना के बाद भागकर उज्जैन आ गया था। गुजरात पुलिस रईस रफीक को गुजरात लेकर गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर जहरीली शराब तैयार करने, शराब की बोतलों पर स्टीकर लगाने और उसकी आपूर्ति करने के आरोप लगाए हैं।



शराब तस्करी के मामले में तराना विधायक महेश परमार ने गुजरात में जब्त शराब की 28 पेटियों पर उज्जैन आबकारी विभाग की साल और मुहर मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

चिंतन का विषय यह है कि मध्यप्रदेश के समीपस्थ राज्य गुजरात, जहां देशी-विदेशी मदिरा पर प्रतिबंध है, उससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि गुजरात में मध्यप्रदेश की शराब मिल जाती है। गुजरात राज्य में शराब पहुंचाने में मध्यप्रदेश के वे जिले शीर्ष पर हैं, जो सीमा से सटे हुए हैं। झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, इन जिलों से प्रतिदिन लाखों रुपयों की शराब का अवैध परिवहन आसानी के साथ किया जाता है। बताते हैं कि इस अवैध परिवहन में सरकार के नुमाइंदों के साथ प्रशासन के बाशिंदों का सहयोग पर्दे के पीछे से पूरा-पूरा रहता है। वहीं पुलिस की जानकारी से अछूता ऐसा एक भी रास्ता नहीं है, जहां से गुजरकर शराब गुजरात नहीं जाती, लेकिन जेब में हाथ और आंखों में माया का नशा कार्रवाई करने में लापरवाही करवा देता है और लाखों की शराब को उस पार पहुंचा देता है।

अवैध व्यापारियों के राजनीतिक संबंधों की मजबूती का अनुमान इस स्थिति से लगाया जा सकता है कि कितनी आसानी से मध्यप्रदेश की मदिरा गुजरात के द्वार से प्रवेश कर राज्य में फैल जाती है। अवैध शराब के अवैध परिवहन पर अधिकारियों के अधिकतर उत्तर यही होते हैं कि समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अगर कहीं अवैध परिवहन या बिक्री पाई गई तो निश्चित ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मगर सिर्फ और सिर्फ ये रटे-रटाए जवाब देने के लिए ही होते हैं। इन वाक्यों को कभी भी मूर्त रूप नहीं दिया जाता।

खातेगांव के थाना प्रभारी को कुचलने वाला मिनी ट्रक अवैध शराब से भरा हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्टी से खातेगांव विधानसभा प्रभारी राहुल जायसवाल है। वह 2018 से 2024 तक हरदा जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुका है। देवास के केमिकलयुक्त शराब कांड में इंदौर के कांग्रेस संभागीय प्रवक्ता आनंद कासलीवाल और उनके बेटे अमन कासलीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर शराब के अवैध कारोबार को केमिकल की आपूर्ति करने का आरोप है।

हालांकि आबकारी विभाग और राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध शराब कारोबारी अपने कार्य में प्रगति कर रहे हैं और बेखौफ प्रदेश में अवैध जहरीली शराब फैला रहे हैं। साथ ही वे शराब गुजरात राज्य के हर गांव में पहुंचा रहे हैं।

बहरहाल, प्रदेश में जहरीली और अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है, तब सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। झाबुआ, आलीराजपुर से प्रतिदिन लाखों की शराब गुजरात जा रही है, गुजरात में उज्जैन की शराब मिल रही है, वहीं मंदसौर, देवास और नीमच की शराब भी गुजरात तक जा रही है, तो सरकार चुप्पी साधे क्यों है। जहरीली शराब से दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, फिर भी अवैध शराब के कारोबार पर प्रदेश सरकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सांदीपनि लोक के लिए आसाराम आश्रम की जमीन ली तो होगा महासंग्राम

माही की गूंज, उज्जैन।

संचालक की चेतावनी- कोर्ट जाएंगे, करेंगे हड़ताल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली को सांदीपनि लोक के रूप में विकसित करने की योजना को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए है। सांदीपनि आश्रम के पास स्थित आसाराम बापू आश्रम की जमीन अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ आश्रम प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है।

आश्रम के संचालक शिवा भाई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आश्रम की जमीन लेकर वहां सांदीपनि लोक बनाया गया, तो वे कोर्ट जाएंगे। हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ने पर देशभर से आसाराम बापू के अनुयायी उज्जैन आकर इस कार्रवाई का विरोध करेंगे।

आसाराम बापू आश्रम के संचालक शिवा भाई का आरोप है कि उनके आश्रम को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आश्रम की जमीन से 80 फीट चौड़ी सड़क निकालने की योजना थी, लेकिन भक्तों के विरोध के बाद प्रशासन को उस सड़क का रास्ता बदलना पड़ा था। अब सांदीपनि लोक के नाम पर फिर से आश्रम की जमीन लेने की कोशिश की जा रही है।

शिवा भाई के अनुसार, आश्रम को अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन कुछ दिनों पहले नायब तहसीलदार शेफाली जैन ने आश्रम आकर सांदीपनि लोक के लिए जमीन लेने की बात कही थी। बैठक के दौरान ही आश्रम प्रबंधन ने साफ कर दिया था कि वे किसी भी कीमत पर यह धार्मिक स्थल नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले स्वयं आसाराम बापू भी आश्रम आए थे और उन्होंने भी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था।

सनातन की सरकार में भी परेशान होना पड़ रहा

आश्रम संचालक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आश्रम में हिंदू संस्कृति को जगाने का काम हो रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां शांति पाने आते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन की सरकार होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही, सरकार की ओर से बापू के स्वास्थ्य लाभ या इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में इस धर्मस्थल को हटाकर सांदीपनि लोक बनाना बिल्कुल उचित नहीं है और वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

139 करोड़ में बनेगा सांदीपनि लोक

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सांदीपनि लोक के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। पहले इसके लिए 15 बीघा जमीन का प्लान था, जिसे अब बढ़ाकर करीब 17 बीघा कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि आश्रम प्रबंधन को धारा 4 के बाद धारा 11 का नोटिस जारी किया जा चुका है। प्रशासन चाहता है कि आपसी सहमति (क्रय नियम) के तहत जमीन मिल जाए, जिससे लगभग दो महीने में ही मुआवजा दिया जा सके। सामान्य अधिग्रहण प्रक्रिया में करीब छह महीने का समय लग सकता है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने लगभग 139 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सांदीपनि लोक के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यहां 9 अलग-अलग थीम जोन बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु और पर्यटक एआर-वीआर और डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की ज्ञान यात्रा और 64 कलाओं को देख व समझ सकेंगे। जमीन उपलब्ध होते ही यूडीए निर्माण कार्य शुरू कर देगा।



लकड़ी तस्करों पर लगातार कार्यवाही जारी

माही की गूंज, धार।

वन मण्डल अधिकारी विजयनंथम टी. आर. के निर्देशन पर वन मण्डल धार में लकड़ी तस्करों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत रात्री वन मण्डल विभाग धार द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर फिर एक बड़ी कार्यवाही की गई। वन मंडल अधिकारी धार द्वारा बताया गया कि लेबड मानपुर फोरलेन पर उडनदस्ता दल द्वारा गस्ती के दौरान 17 नवंबर 2026 को सुबह 5-30 बजे के आसपास लेबड की ओर से आते हुए एक संदिग्ध आयसर वाहन यूपी 30 एटी 4101 को रोका गया और उसकी जांच की गई। वाहन में पंचमेल जलाऊ के ताजे कटे गुल्हे लगभग 10 टन भरे हुए होना पाये गये। वाहन चालक से पुछताछ करने पर अपना नाम मांगीलाल पिता सेवकराम निवासी गौतमपुरा बताया गया एवं वाहन मालिक का नाम प्रकाश पिता नानुराम निवासी गौतमपुरा बताया गया। लकडी के बारे में पूछताछ पर बताया गया कि उसके द्वारा सोहराब भाई निवासी बडनगर के कहने पर कुलदीप पांचाल की बडनगर स्थित आरामशीन से भरकर पिथमपुर स्थित श्री पेपर कम्पनी ले जा रहा था। वाहन चालक से लकडी कटाई एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र दस्तावेज मांगे गए उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया गया। तत्काल टीम द्वारा मौका की कार्यवाही की गई एवं वाहन को रेंज केम्पस धार लाया गया जिसकी जांच कार्यवाही की जा रही है। वन स्टाफ परिक्षेत्र धार का उक्त कार्यवाही मे उल्लेखनीय योगदान रहा।



शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर समीक्षा

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त विकासखंडों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड स्रोत समन्वयकों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, उपयोग योग्य शौचालय तथा विद्यार्थियों को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाए,ताकि बच्चों को सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय छोड़ चुके छात्र-छात्राओं का विकासखंडवार डाटा तैयार कर उनके स्कूल छोड़ने के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाए। यदि कोई विद्यार्थी अपने माता-पिता के साथ रोजगार अथवा अन्य कारणों से दूसरे स्थान पर पलायन कर गया है, तो उसके अभिभावकों से संपर्क कर संबंधित स्थान पर ही उसकी शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं, अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित हुए बच्चों को चिन्हित कर पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करने तथा विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न पोर्टल पर निर्धारित जानकारियां समय-सीमा में दर्ज की जाएं। सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी संकलित कर उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति अथवा अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।



शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कलेक्टर श्रीमती माथुर ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं सहित अन्य कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने तथा उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए अधिक से अधिक लिखित अभ्यास कराया जाए, ताकि परीक्षा के दौरान वे आत्मविश्वास के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाए, जिससे उनका उत्साह एवं आत्मविश्वास बढ़े और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिले।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सभी शाला प्रमुखों को निर्देशित किया कि कमजोर विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय की जाए। इसके लिए प्रत्येक कमजोर विद्यार्थी को एक शिक्षक के मार्गदर्शन में देकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं के माध्यम से अधिकाधिक लिखित अभ्यास कराया जाए तथा उनकी विषयवार कठिनाइयों का निरंतर समाधान किया जाए।

उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार करवाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी और वे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा केन्द्र, डीपीसी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वच्छता के पीछे सफाई मित्रों की मेहनत

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन की स्वच्छता और शहर की पहचान के पीछे सफाई मित्रों की मेहनत, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की अहम भूमिका रही है। जब पूरा शहर रात में आराम कर रहा होता है, तब सफाई मित्र पूरी निष्ठा के साथ सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा बनाने में जुटे रहते हैं। उनकी इसी मेहनत के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है।

उज्जैन में कोरोना महामारी का कठिन दौर रहा हो या महाकाल की सवारी जैसे बड़े धार्मिक आयोजन, सफाई मित्रों ने हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नागपंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर जब शहर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है, तब सफाई व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे समय में सफाई मित्र दिन-रात काम करते हुए शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

बड़े आयोजनों में भी नहीं डगमगाया सफाई मित्रों का हौसला

महाकाल की सवारी, नागपंचमी और महाशिवरात्रि उज्जैन के प्रमुख धार्मिक आयोजन हैं। इन अवसरों पर देशभर से श्रद्धालु शहर पहुंचते हैं। भीड़ बढ़ने के साथ ही सड़कों, मंदिर मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सफाई मित्र इन चुनौतियों के बीच लगातार काम करते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सके।



कोरोना काल में भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया। संक्रमण के खतरे के बीच उनकी सेवाएं शहर के लिए महत्वपूर्ण रहीं। यही वजह है कि उज्जैन की स्वच्छता की चर्चा में सफाई मित्रों के योगदान को विशेष महत्व दिया जाता है।

सामूहिक प्रयास से मिला उज्जैन को सम्मान

उज्जैन को मिला सम्मान केवल किसी एक विभाग या व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और शहर के प्रत्येक नागरिक का सहयोग शामिल है। स्वच्छता के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी होती है। शहर को साफ रखने के लिए सफाई व्यवस्था के साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता होना भी महत्वपूर्ण है।

सफाई मित्रों की मेहनत के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग तथा नागरिकों की सहभागिता ने उज्जैन की स्वच्छता व्यवस्था को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है।

सफाई मित्रों के योगदान को पहचानना जरूरी

शहर की स्वच्छता केवल सड़कों पर कचरा उठाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे रोजाना मेहनत करने वाले उन कर्मचारियों का योगदान है, जो अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहकर अपना काम करते हैं। सुबह शहर के जागने से पहले ही कई सफाई मित्र अपने काम में जुट जाते हैं।

उज्जैन की स्वच्छता और उसे मिले सम्मान के पीछे इन्हीं कर्मचारियों का श्रम और समर्पण भी शामिल है। शहरवासियों के सहयोग से ही स्वच्छता की यह व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। सफाई मित्रों के काम को सम्मान देना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

मतदाता जागरूकता अभियान

माही की गूंज, आलीराजपुर।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, क्रांतिकारी शहीद छीतूसिंह किराड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आलीराजपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के माध्यम से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत प्रत्येक संस्था स्तर पर निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दो-दो विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. मीना सोलंकी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मताधिकार के सही उपयोग तथा निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को स्वयं जागरूक बनने और समाज के अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 18 नवंबर 2026 को जिला स्तर पर अंतिम चरण की निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र जोबट से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चार विद्यार्थियों तथा विधानसभा क्षेत्र आलीराजपुर से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छह विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस प्रकार दोनों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 10 विद्यार्थियों का अंतिम चरण के लिए चयन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के अधिकार एवं जिम्मेदार नागरिकता के प्रति समझ विकसित करना तथा युवा पीढ़ी को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस कार्यक्रम में डॉ. सी. एस. कनेश डॉ. सुरेश तोमर, डॉ. संतोष सूर्यवंशी, ईएलसी के नोडल अधिकारी प्रो. भावसिंह डावर सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



धार-इंदौर के बीच यात्री ट्रेन संचालन को मिली हरीझंडी

माही की गूंज, धार।

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार से इंदौर के बीच यात्री ट्रेन शुरू होने का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच के बाद 16 नवंबर को धार-इंदौर रेलखंड पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दोनों के संचालन को अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में दिसंबर में यात्री ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, धार को फिलहाल इंदौर से जोड़ने के लिए मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन ही प्रमुख विकल्प होगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन अथवा इंदौर से चलने वाली ट्रेनों का धार तक विस्तार फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है।



बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लंबी दूरी की ट्रेनों का विस्तार मुश्किल

दरअसल, कुछ समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि इंदौर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यातायात और सीमित सुविधाओं को देखते हुए कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का विस्तार धार तक किया जा सकता है। इससे धार को भी लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी मिल सकती थी, लेकिन इसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पिट लाइन और कोच वाटरिंग हाइड्रेंट की व्यवस्था है।

क्या होती है पिट लाइन और हाइड्रेंट सुविधा

पिट लाइन रेलवे ट्रैक के नीचे निरीक्षण और रखरखाव के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से ट्रेन के डिब्बों के निचले हिस्से, पहियों, ब्रेक और अन्य तकनीकी उपकरणों की जांच, मरम्मत तथा कोचों की सफाई की जाती है। लंबी दूरी की ट्रेनों के अगले फेरे से पहले उनकी निर्धारित देखरेख के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण होती है। वहीं, कोच वाटरिंग हाइड्रेंट ऐसी पाइपलाइन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे की पानी की टंकियां भरी जाती हैं।

इससे यात्रियों को शौचालय और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाता है। धार में इन दोनों सुविधाओं का अभाव होने से लंबी दूरी की ट्रेनों के रैक का रखरखाव, सफाई और पानी भरने जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर करना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि फिलहाल यहां से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन या अन्य ट्रेनों का विस्तार व्यावहारिक नहीं दिख रहा है।

राजनीतिक स्तर पर भी पहल जरूरी

बता दें कि 5 और 6 नवंबर को रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने रेलखंड का निरीक्षण किया था। इसके बाद आवश्यक औपचारिकताओं के साथ संचालन की अनुमति मिली है। अब दिसंबर में ट्रेन शुरू करने को लेकर उम्मीदें हैं। हालांकि, इसके लिए राजनीतिक स्तर पर भी पहल जरूरी होगी।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की ओर से रेलवे मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शीघ्र ट्रेन संचालन के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही भविष्य में लंबी दूरी की ट्रेनों का लाभ धार को मिल सके, इसके लिए पिट लाइन और हाइड्रेंट जैसी सुविधाओं के विकास की मांग भी उठानी होगी।

जिला प्रशासन का अपनी ढपली अपना राग, मंत्री भी कहे मिले सुर मेरा तुम्हारा

तय समय से लेट नर्मदा मय्या का जल और ऊंट पर बैठकर बकरियां चराते मंत्री और जिला प्रशासन

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

जिला प्रशासन और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री शायद उंट पर बैठकर बकरी चराते ही नजर आ रहे हैं। अक्सर यह देखा गया है कि, किसी योजना और आयोजन को लेकर जिला प्रशासन इतना उत्साहित हो जाता है कि, वह कार्य शुरू होने के पहले ही ढिंढोरा पीटने लग जाता है। नतीजा यह होता कि, या तो वह योजना या आयोजन लेट हो जाते है या फिर सिरे से खारिज। मगर प्रशासन का रवैया तो हमेशा से ही अपनी ढपली अपना राग रहा है, सो वह आदत से मजबूर है। लेकिन जब प्रशासन की ढपली और राग में सरकार के मंत्री ही लपेटे में आते नजर आए तो मंत्रियों और सरकार का ढोल बजना भी तय हो जाता है।

ऐसी ही स्थिति पिछले दिनों मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में देखने को मिली। जब नर्मदा नदी का जल झाबुआ की सीमाओं में प्रवेश करने वाला था। जिला प्रशासन ने इसे लेकर पहले ही एक आयोजन कर डाला, जिसमें जिन ग्रामों से होकर नर्मदा जल गुजरेगा उन ग्रामों के ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। इस आयोजन में बकायदा प्रशासन मध्यप्रदेश सरकार की केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया को भी शामिल किया। आयोजन में उपस्थित लोगों को जिला प्रशासन ने नर्मदा जल के लाभ गिनाए और इसे व्यर्थ न बहाने की समझाईश दी। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि, 15 नवम्बर जनजातिय दिवस के शुभ अवसर पर नर्मदा मय्या का जल जिले में प्रवेश करेगा जो कि बहुत ही शुभ है। मंत्री निर्मला भूरिया ने भी कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को नर्मदा मय्या की जल धारा का स्वागत करने की अपील की। इस अवसर पर कई तरह के आयोजन, कलश यात्रा और मंत्रोच्चार के साथ नर्मदा मय्या के जल का स्वागत करने की बात ग्रामीणों से कही।

सारी तैयारियां धरी कि धरी रह गई

मगर इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि, खुद जिला प्रशासन और सरकार की केबिनेट मंत्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 15 नवम्बर जनजातिय गौरव दिवस के अवसर पर जिले में नर्मदा जी का जल पहुंच ही नहीं पाएगा। सारी तैयारियों के बावजूद जिले में 15 नवम्बर को नर्मदा मय्या का जल तो ठीक उसकी एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई और जिला प्रशासन और ग्रामीणों की स्वागत तैयारियां धरी के धरी रह गई। कारण जो भी हो लेकिन यहां यह तो स्पष्ट हो गया कि, जिला प्रशासन और सरकार के मंत्री ऊंट पर बैठकर बकरियां ही चरा रहे है।

पता ही नहीं था कि 15 नवम्बर को नर्मदा क जल जिले में पहुंच ही नहीं रहा

जब जिला प्रशासन झाबुआ में 14 नवम्बर को जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नर्मदा झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत जिले के लाभान्वित 194 ग्रामों के ग्रामीणों और कृषकों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम कर समनवय बैठक कर रहे थे। तब तक उन्हे यह पता ही नहीं था कि, जिले में नर्मदा का जल 15 नवम्बर को पहुंच ही नहीं रहा है। मगर जिला प्रशासन अपनी ढपली अपना राग गाता रहा और सरकार की केबिनेट मंत्री जिला प्रशासन के सुर में सुर मिलाती रही ''मिले सुर मेरा तुम्हारा''।



९४ नवम्बर को जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के आडिटोरिम में हुए शासकीय कार्यक्रम में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने बिना जाने यह घोषणा कर दी कि ९५ नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर जिले में नर्मदा जी जल पहुंचेगा और सभी ग्रामीण किसान कलश यात्रा निकालकर, मंत्रोच्चार और विधि विधान से नर्मदा जल का स्वागत करें। लेकिन ९५ तो ठीक अब तक नर्मदा जी का जल जिले में एक बूंद भी नही पहुंच पाया। अब भी शायद जिले के किसानों को शनिवार तक नर्मदा मय्या के जल का इंतजार करना पड़ेगा।

इंतजार करते रह गए जिले के किसान

जब लोगों को 15 नवम्बर को नर्मदा जी के जल का बेसब्री से इंतजार था तब स्थिति यह बनी कि जनजाति गौरव दिवस का शुभ अवसर निकल गया और नर्मदा जल अंत तक भी जिले की सीमाओं में नहीं पहुंच सका। लोग इंतजार ही करते रह गए। अब गलती कहां हुई यह एक अलग विषय है लेकिन जिला प्रशासन और केबिनेट मंत्री की स्थिति खिसयाई बिल्ली खंबा नौचे वाली दिखाई दे रही है। अब मंत्री जी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब तलब करने में लगी हुई है।

एक सप्ताह का इंतजार

उधर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंत्री जी को सीधा सा जवाब दे दिया कि, झाबुआ जिले को अब नर्मदा जल के लिए एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। इस सारे घटनाक्रम ने जिला प्रशासन और केबिनेट मंत्री के ढोल की पोल खोल दी है और हर कोई यह समझ चुका है कि, जिला प्रशासन और मंत्री उंट पर बैठकर बकरियां चरा रहे है।

व्यवस्थाएं ढाक के तीन पात

उधर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की स्थिति भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रही है। क्योंकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की झाबुआ जिले में नर्मदा जल पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी ढाक के तीन पात साबित हो रही है। जब तय समय के अनुसार झाबुआ जिले को नर्मदा जल पहुंचाना था तो फिर यह आधे रास्ते में ही क्यों रूक गया। बताया जाता है कि, झाबुआ जिले को मिलने वाला नर्मदा जल धार जिले के किसानों ने ही जबरन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लिया। जबकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी मुकदर्शक बनकर रह गए।

धार जिले के किसानों ने लाइन के वाल्व खोलकर ले लिया पानी

जिस परियोजना की पाइप लाइन से नर्मदा का जल झाबुआ जिले को मिलने जा रहा है वह पाइप लाइन धार जिले से होकर गुजर रही है। जब एनवीडीए (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) ने झाबुआ के लिए नर्मदा जल पाइप लाइन में छोड़ा तो धार जिले के किसानों ने इस पाइप लाइन के वाल खोल दिए और झाबुआ जिले में आने वाला नर्मदा जल धार जिले की सीमा तक ही सिमट कर रह गया। धार जिले के किसानों ने सिंचाई की आवश्यकता बताते हुए पाइपलाइन के वाल्व कई जगह से खोल लिए और पानी अपने खेतों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। वे पहले अपने क्षेत्र में पानी देने की मांग कर रहे थे। मगर इधर झाबुआ जिले के किसान भी अपनी फसलों में सिंचाई को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे है। जिले के करीब 194 गांवों के किसान नर्मदा जल का इंतजार करते दिखाई दे रहे है। अब जबकि नर्मदा का वह जल जो झाबुआ पहुंचना था धार के किसानों ने उपयोग कर लिया तो एनवीडीए के अधिकरियों ने धार जिले के लिए एक सप्ताह का अलग शेड्यूल तय किया है। जिसके बाद ही जिले की ओर नर्मदा जल की आपुर्ति शुरू की जाएगी। जिले के किसानों को अब नई समय सारणी के अनुसार पानी मिलने का इंतजार है।

यह समस्या कहीं हर बार की तो नहीं...?

मगर एक सवाल फिर नया सामने यह आ खड़ा हुआ है कि, अगर एनवीडीए ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो झाबुआ जिले के ग्रामीणों और किसानों को इस तरह की समस्या का कहीं हर बार सामना न करना पड़े। क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरूआत ही है, जब धार जिले के किसानों ने झाबुआ जिले का पानी रोक लिया और पाइप लाइन के वाल्व खोलकर अपने खेतों तक पानी पहुंचा दिया। अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो यह कहानी हर बार दोहराई जासकती है और झाबुआ के किसान नर्मदा जल के लिए टकटकी बांधे रह जाएंगे।

तो जिला प्रशासन अपनी ढपली अपना राग बंद करे और प्रदेश सरकार की मंत्री प्रशासन के साथ सुर से सुर मिलाना छोड़े और उंट पर बैठकर बकरियां चराना बंद करे। ताकि भविष्य में जिले को मिलने वाले नर्मदा जल से जिले के किसानों को सही से लाभ मिल सके। वरना जो जिले के किसानों के साथ होगा वह हम अभी से देख और समझ रहे है...।

लापता खवासा सरपंच गंगाबाई...?

माही की गूंज, खवासा।

किसी भी ग्राम या नगर में उस गाँव व नगर के मुखिया की सजगता व लोगों से जीवित संपर्क होता है तो ही गाँव में मुखिया के प्रति विश्वास होकर लोगों में उत्साह होकर विकास की उम्मीद लगी रहती है। लेकिन जिस गाँव व नगर का मुखिया, वोट लेकर बन जाता है। परंतु वह अपने जीवित संपर्क से दूरी बना लेता है तो लोगों का विश्वास खत्म होने के साथ विकास की उम्मीदें भी खो बैठते हैं।



बात करे ग्राम पंचायत खवासा की सरपंच महोदया गंगाबाई खराड़ी की तो, ग्राम में उनका जीवित संपर्क नहीं होने के चलते कहने लगे हैं कि सरपंच गंगाबाई खराड़ी लापता हो गई है...? अगर किसी को दिखें तो सरपंच महोदया को अवगत कराएं कि ग्राम खवासा अतिक्रमण के साए में है, खवासा का बाईपास जो अतिक्रमण की चपेट में आकर अवरुद्ध हो रहा है, पंचायत द्वारा बनाई गई चार दुकानें जो बाजना मार्ग पर स्थित है जिसकी निलामी की जाए, पुरानी ग्राम पंचायत पर दुकाने बनाने हेतु पुराने भवन को तोड़ जमींदोज कर दिया है जिसे आपके कार्यकाल में उक्त स्थान पर दुकान बनाया जाना था उसे बनाएं, बस स्टैंड पर सड़क निर्माण के साथ यात्री प्रतीक्षालय जमींदोज हो गया है और यात्री प्रतीक्षालय की आस लगाए बैठे हैं लोगों को पंचायत की योजना के अंतर्गत यात्री प्रतीक्षालय बनाकर लोगों को सुविधा दी जाए, करीब चार करोड़ की लागत से पुनः खवासा की पेयजल व्यवस्था के निदान हेतु कूप खनन, पाइपलाइन व एक और टंकी का निर्माण किया गया है उस योजना का लाभ लोगों को प्रतिदिन नल में पानी देकर सुविधाएं दी जाएं, ठेकेदार द्वारा गाँव में जो सीसी रोड पाइपलाइन करने के बाद बनाए गए हैं वह भ्रष्टाचार की धूल उड़ा रहे हैं उस धूल से मुक्ति दिलाने का प्रयास सरपंच महोदया द्वारा किया जाए। आदि इन सारी समस्याओं से अनजान सरपंच महोदया गंगाबाई को अवगत करवाने हेतु आमजन सरपंच महोदया को धार्मिक आयोजन जैसे नवरात्रि, 10 दिवसीय गणेश महोत्सव, शिवरात्रि, हनुमान जयंती आदि अवसरों के साथ किसी शोकाकुल परिवार के यहाँ बैठक के दौरान, धार्मिक एवं मांगलिक आयोजन में भी सरपंच महोदया दिखें तो गाँव की समस्या से अवगत अनुरोध के साथ करवाएं की मंशा लोगों के मन में है। लेकिन सरपंच महोदया सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के दौरान झंडा वंदन समारोह के अलावा ग्राम पंचायत में तो ठीक, किसी भी तीज-त्योहार या कहीं किसी के आयोजन में नहीं दिखाई देती हैं न ही ग्राम में किसी से कोई जे रामजी की। जिसके चलते सरपंच के प्रति लोगों के मन में मायूसी छाई रही है। वहीं सरपंच पुत्र शंकर खराड़ी सरपंच प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहा है, वह भी गाँव की गतिविधियों से दूरी बनाए रखा हुआ है। जबकि शंकर खराड़ी के सरल स्वभाव के चलते ही आम जनता में उम्मीद जताई थी कि, शंकर खराड़ी, माँ गंगाबाई सरपंच बनने के बाद गाँव के प्रभुत्वजनों से सलाह-मशवरा करने के बाद गाँव में विकास की धारा बहाएगा। लेकिन यहाँ भी लोगों की उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दी गई और सरपंच को सारी गतिविधियों से दूरी होने के चलते लापता घोषित किया जा रहा है...!

ग्राम खवासा की ज्वलनशील एवं पुरानी पेयजल समस्या से स्थाई निजात, तथा क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत को पूरा किया जाए, की उम्मीद के साथ 16 नवंबर से अनिश्चित धरना किया जा रहा है। लेकिन इस गतिविधि से भी सरपंच महोदया गंगाबाई खराड़ी व पुत्र सरपंच प्रतिनिधि शंकर खराड़ी भी दूरी बनाए हुए हैं। जिसके चलते अब धरने पर बैठी महिलाए व लोग भी कह रहे हैं कि, सरपंच गंगाबाई कहीं लापता हो गई है उसे ढूंढकर लाओ और गाँव की समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ सरपंच महोदया को अवगत करवाओ...!

बंद पड़ी तहसील और गार्डन बना प्रेमी जोड़ों का अड्डा

स्कूल ड्रेस में पार्क में घूमते बच्चे, नगर में आक्रोश





माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

कस्बे के बीचों-बीच स्थित पुरानी तहसील कार्यालय का भवन और वहा स्थित गार्डन अब चर्चा का विषय बन चुका है। नए तहसील भवन में कार्यालय शिफ्ट होने के बाद से कार्यालय बंद पड़ा है। देखरेख के अभाव में यह भवन अब खंडहर में बदलता जा रहा है। इससे लगा हुआ नगर का गार्डन अब बच्चों के खेलने की जगह कम, और प्रेमी जोड़ों के मिलने का सुरक्षित स्थान ज्यादा बन गया है। दिन भर इस गार्डन ओर इसके आसपास प्रेमी जोड़े विचरण करते नजर आते है। साथ ही स्थानीय कई स्कूलो के बच्चे भी स्कूल टाइम पर इस सुने भवन और गार्डन में नजर आते है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि, दिन के समय ही गार्डन और सूने तहसील भवन के आसपास ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले सभ्य परिवारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सबसे चिंता की बात यह है कि स्कूल के समय में कई बच्चे स्कूल ड्रेस में ही इस पार्क में घूमते हुए दिखाई देते हैं।



बच्चे स्कूल के नाम से घर से निकलते हैं, पर स्कूल न जाकर यहां आ जाते हैं

यहां का माहौल देखकर हमें बच्चों की चिंता लाजमी है, एक स्थानीय अभिभावक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, इस प्रकार के माहौल में बच्चे एक-दूसरे के साथ बिगड़ते है, कई बाहरी और ग्रामीण युवा इस क्षेत्र में घुमते रहते है तथा स्कूल की लड़कियों को निशाना बनाते है। लोगों का आरोप है कि, सूने भवन और गार्डन में न तो कोई चौकीदार है, न ही पुलिस की नियमित गश्त होती है। इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व दिन-दहाड़े यहां जमा हो जाते हैं।

नगरवासियों की मांग

नगरवासियों ने सुने तहसील भवन और गार्डन को या तो फिर से उपयोग में लाया जाए, या उसे सील करके उसकी सुरक्षा की जाए। गार्डन में चौकीदार की नियुक्ति हो और स्कूल समय में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए तथा स्कूल ड्रेस में घूमते बच्चों पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक ध्यान दें। यदि प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया, तो यह स्थान बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

नगर विकास के लिए नई योजना जरूरी, क्षेत्र में व्यापार हुआ कमजोर

तहसील कार्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लंबी चौड़ी भूमि एक के बाद एक शासकीय भवनों के अन्यत्र स्थान पर जाने से सुनी पड़ी है। रायपुरिया रोड से लेकर गांधी चौक तक कई व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वही आम जनता को भी अब अपने कामों के लिए नगर से बहार अलग-अलग दिशा में जाना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि, उक्त सुने पड़े परिसर में बड़े प्रोजेक्ट की स्थापना जैसे सब्जी मंडी, पार्किंग या बस स्टेशन बनाया जाए जिससे नगर की जनता को अतिक्रमण से होने वाली परेशानी से राहत मिले और इस क्षेत्र का व्यापार एक बार फिर बढ़ सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422